लखनऊ

शनिवार, 23 मई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 267

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

समझनी है जिंदगी तो पिछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो... ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है।

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होगा मतदान, आयोग ने किया चुनाव की तारीख का एलान

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 रिक्त सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 18 जून को मतदान होगा, जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि राज्यसभा चुनाव 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए कराए जाएंगे। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। झारखंड में दो सीटों पर, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर चुनाव होंगे। राज्यसभा के जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कूरियन और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए निगरानी यंत्र नियमों में बड़ा बदलाव, यात्रा सुरक्षा को मिलेगा नया बल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवा वाहनों में यात्रा को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निगरानी आधारित बनाने के उद्देश्य से वाहन स्थिति निगरानी यंत्र (वीएलटीडी) को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शासन ने एक जनवरी 2019 से पहले और बाद में पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए नए निर्माताओं के पंजीकरण, पुराने मॉडलों में संशोधन तथा कुछ कंपनियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को मंजूरी दी है, ताकि वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों को यंत्र लगाने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ हो सके।यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थिति निगरानी यंत्र लगाने और उसे सक्रिय करने को लेकर शासन ने व्यापक निर्णय लिए हैं। नए निर्माताओं और मॉडलों को अनुमति देने के साथ पहले से स्वीकृत कंपनियों के वाहनों एवं मॉडलों में विस्तार, संशोधन और कुछ मामलों में विलोपन का अनुमोदन भी किया गया है।मंत्री ने बताया कि नई स्वीकृत कंपनियों में पीएसडीएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को स्टेलेंटिस कंपनी के वाहनों में अपने यंत्र लगाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार एक्यूट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एपीएम समूह प्राइवेट लिमिटेड तथा एपीएम किंग्सट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के वाहनों में निगरानी यंत्र लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है।

अमित शाह ने 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना की घोषणा की, घुसपैठियों को बाहर करने की शून्य-सहिष्णुता नीति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की कि सरकार सीमा पार घुसपैठ के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। उन्होंने बताया कि देश की सीमाओं को सील करने और सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए एक व्यापक स्मार्ट बॉर्डर परियोजना इस वर्ष शुरू की जाएगी। शाह ने कहा कि अवैध प्रवासन जनसांख्यिकीय बदलाव लाने की एक सोची-समझी साजिश है, और सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करेगी।

विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पदग्रहण समारोह 2026 को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही। गृह मंत्रालय देश की 6,000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एक अभेद्य सुरक्षा ग्रिड लागू करेगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले एक वर्ष के भीतर, स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत, बीएसएफ को ड्रोन रडार और उन्नत कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह मंत्री ने बीएसएफ से आग्रह किया कि वह घुसपैठ और पशु तस्करी के मार्गों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए राज्य पुलिस, जिला कलेक्टरों और ग्राम पटवारियों के साथ सीधे समन्वय करके अपने खुफिया नेटवर्क का विस्तार करे।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सरकारों के साथ नीतिगत तालमेल इस सुरक्षा ग्रिड को सुविधाजनक बनाएगा। गृह मंत्रालय जल्द ही इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाएगा। वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन का उदाहरण देते हुए शाह ने कहा, किसी समस्या को नियंत्रित करना सुरक्षा नहीं है; उसे जड़ से खत्म करना ही सही तरीका है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीमा पर तैनात जवानों की सहायता के लिए जल्द ही एक उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन शुरू किया जाएगा। शाह ने बीएसएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि 1965 में 25 बटालियनों के साथ शुरू हुआ यह बल अब 2,70,000 कर्मियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बन गया है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्तव्य के दौरान उत्कृष्ट योगदान और सर्वोच्च बलिदान के लिए बीएसएफ कर्मियों को सम्मानित भी किया।

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया

नई दिल्ली, एजेंसी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या उसमें लिप्त व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें ताकि रेलवे को निशाना बनाने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। रेलगाड़ियों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देश भर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। रेल भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। हाल ही में हुई आगजनी की कुछ घटनाओं सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इनकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, रेलवे मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

'कुसंस्कार और कुंठा', पीएम मोदी पर अजय राय के बयान पर भड़के सीएम योगी, कहा- ये लोग माफी लायक भी नहीं बचे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है। अजय राय ने पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यना ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के 'युवराज' भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियापन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है।

अजय राय ने महोबा दौरे के दौरान गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लौटते समय अजय राय ने कांग्रेस कार्यकर्ता से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। बातचीत के दौरान अजय राय गाली का इस्तेमाल किया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद अजय राय ने इसे फेक और एडिटेड बताया। वीडियो से एआई से बनाना बताया। बता दें कि एक मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य की कामना की थी।

आतंकवाद मामलों में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 'घमासान'

अजमल कसाब और हाफिज सईद का नाम लेकर केंद्र ने अदालत से पूछे सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में जमानत को लेकर अलग अलग पीठों के फैसलों के बीच अब यह सवाल और गंभीर हो गया है कि क्या आतंकवाद जैसे मामलों में भी 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' का सिद्धांत उसी तरह लागू होगा। केंद्र सरकार ने आज इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने की जोरदार मांग की। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले के आरोपित तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत याचिकाओं के साथ-साथ इस सवाल पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या इस पूरे विवाद को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आदेश बाद में या 25 मई को सुनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि जमानत का फैसला हर मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केवल लंबे समय तक जेल में रहने को आधार मान लिया जाए तो फिर गंभीर आतंकवादी मामलों में भी जमानत देनी पड़ेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकवादी हमले का दोषी अजमल कसाब कई वर्षों तक मुकदमे के कारण जेल में रहता, तो क्या उसे भी जमानत मिल जाती। इसी तरह उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि विदेश से साक्ष्य जुटाने में समय लगे और मुकदमा लंबा चले, तो क्या केवल पांच वर्ष जेल में रहने के कारण उसे भी रिहा कर दिया जाएगा। राजू ने अदालत के सामने यह भी कहा कि हाल के फैसले में अपराध की प्रकृति और आरोपित की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और ऐसे मामलों में सामान्य आपराधिक मामलों जैसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। उनका कहना था कि अदालत को हर मामले की गंभीरता, आरोपित की भूमिका, मुकदमे की स्थिति और देरी के कारणों को साथ में देखना चाहिए।

बिहार में 'सुशासन' से समझौता नहीं, एनकाउंटर विवाद पर सीएम सम्राट ने तेजस्वी को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर राजनीति तब और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर राज्य में हाल ही में अपराधियों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई से संबंधित आरोपों को लेकर पलटवार किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में 'जाति आधारित मुठभेड़ें' की जा रही हैं और दावा किया कि अपराधियों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इन आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया और उनकी टिप्पणियों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अब कह रहे हैं कि अगर पुलिस मुठभेड़ होती है, तो पुलिस को पहले अपराधी की जाति पूछनी चाहिए। मैं पुलिसकर्मियों से कहूंगा - ठीक है, पहले उनकी जाति पूछो और फिर गोली चलाओ। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे चौधरी ने अपने हमले को जारी रखते हुए कहा कि ऐसे बयान "सामान्य ज्ञान" से परे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में सुशासन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पटना में पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि

सुवेंदु अधिकारी पीए केस में 'गलत' गिरफ़्तारी पर भड़के सिसोदिया, बोले- भाजपा किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद शुक्रवार को एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मामले में गिरफ्तारियों के संचालन पर सवाल उठाए।

सिसोदिया ने लिखा कि सिंह और उनका परिवार भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ों, ईडी-सीबीआई की छापेमारी और फर्जी मामलों में गिरफ्तारियों का भी जमकर समर्थन किया होगा। उन्होंने इन सब पर भी तालियां बजाई होंगी। भाजपा को उनकी तालियों से और भी ज्यादा हिम्मत मिली होगी - कि जब चाहे, जिस आरोप में चाहे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, मुठभेड़ कर सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर राज सिंह को रिहा नहीं किया जाता तो "अंधभक्त मीडिया" "पुलिस द्वारा आरोपी को गोली मारने" की घटनाओं को प्रचारित कर देता। लेकिन शुक्र है भगवान का। वे बच गए। वरना, भाजपा के अंधभक्त मीडिया पूरे देश में शोर मचा रहा होता कि भाजपा की पुलिस ने मास्टरमाइंड को मार गिराया है। भाजपा के लिए जो वाहवाही वे दे रहे थे, वही उनके अपने ही मुठभेड़ में गोलियों में तब्दील होने वाली थी। हत्या मामले में गिरफ्तार राज सिंह के इस आरोप के बाद ये बयान सामने आया है कि पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया था और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया

'नीट यूजी परीक्षा 100 फीसदी एरर फ्री होगी', जागरण भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने, 'कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते थे कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो देश के शिक्षा माफिया के चंगुल में फंस जाए। इसलिए हमने नीट परीक्षा को रद किया। लोकतंत्र में हम वचनबद्ध हैं ,देश के सामने 21 जून को जो परीक्षा होगी उसको शत प्रतिशत एरर फ्री करना यह हमारा दायित्व है।'

अभी देश में 22 लाख बच्चों को मानसिक यंत्रणा हुई है, उस यंत्रणा को समझते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूं, हमें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े, और इस बार की जेईई यूजी-नीट परीक्षा को रद करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि एजूकेशन में जो गड़बढ़ लोग हैं, जो पेपर माफिया हैं, उनके षणयंत्र में हमारा एक भी छात्र अपने अधिकार से वंचित हो। हमारा दायित्व इसको व्यवस्थित करना है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारा दायित्व समस्या को देखकर आंख बंद करना नहीं है, हमारा दायित्व लोकतंत्र में जिम्मेदारी का है। हम देश के सामने वचनबद्ध हैं कि 21 जून को जो नीट की परीक्षा होगी उसे शत प्रतिशत एरर फ्री कराएंगे। ये हमारा दायित्व है।

न्यू एजूकेशन पॉलिसी पर क्या बोले प्रधान?

धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से लेकर न्यू एजूकेशन पॉलिसी तक का जिक्र किया। कश्मीर की सरस्वती ज्ञान परंपरा से लेकर ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम और कोणार्क के सूर्य मंदिर तक की ऐहिसिकता का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक कारणों से भारतीय शिक्षा को मैकाले की शिक्षा पद्धिति की ओर मोड़ दिया।

न्यू एजूकेशन पॉलिसी के तहत मातृभाषा में शिक्षा पर जोर- धर्मेंद्र प्रधान

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए न्यू एजूकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया। कक्षा 10 तक 3 भाषाओं को पढ़ाने की योजना है।'

मैं बच्चों को पांच विदेशी भाषा पढ़ने का पक्षधर- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं बच्चों को पांच विदेशी भाषा पढ़ने का पक्षधर हूं, जिन बच्चों को विदेश में व्यापार करना है या विदेशियों से डील करनी है उन्हें विदेशी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन सब पर थोपी नहीं जानी चाहिए। भारतीय भाषाएं इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भारत में पिछले 10 सालों में इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं।

'लोकतंत्र में यह मूर्खता है ...' : कॉकरोच जनता पार्टी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर

नई दिल्ली, एजेंसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ' कॉकरोच जनता पार्टी ' हैंडल ने जो सनसनी मचाई है, उसपर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसकी तुलना प्रेशर-कूकर के वॉल्व से की है और कहा है कि लोकतंत्र में इसे दबाना मूर्खता है।

इंस्टाग्राम पर जिस रफ्तार से 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम के हैंडल के फॉलोअरों की संख्या बढ़ी है, उसने दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है। भारत में तो यह सिसासी गलियारों में तो यह सोशल मीडिया पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके समर्थन और विरोध दोनों में ही तरह-तरह की दलीलें दी जा रही हैं।

इसी कड़ी में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी आगे आए हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है, जिसकी शुरुआत में उनका कहना है,'बहुत सारे यूजर्स ने इसे पाकिस्तान-निर्मित साजिश बताकर खारिज किया है, लेकिन वह बहुत ज्यादा सरल है, अभिजीज दीपके ने इसके विरोध में दावा किया है कि उनके 94% फॉलोअर्स भारत में हैं।' सच जो भी हो (और शायद इंस्टाग्राम को इसका सही रिकॉर्ड देना चाहिए), मेरा कहना है कि लोकतंत्र में इसे दबाना मूर्खता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जन भावनाओं, कुंठा और शिकायतों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इन्हें किसी व्यंगात्मक साइट पर प्रसारित होने देना राष्ट्रहित में है।

थरूर ने आगे लिखा है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापकों की सोच जो भी रही हो, लेकिन 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने देश के युवाओं में राष्ट्रीय भावना की एक महत्वपूर्ण धारा को जगाया है।' देश के 'लोकतंत्र के संरक्षक होने के नाते सरकार और विपक्ष दोनों को ही सावधानी से इनकी बातें सुननी चाहिए। इनका जो भी असंतोष है उसका समाधान करना चाहिए।'

'ऐसे आंदोलन प्रेशर-कूकर के वॉल्व की तरह'

शशि थरूर ने आगे कहा है कि 'इस तरह के आंदोलन प्रेशर-कूकर के वॉल्व की तरह होते हैं, जो भाप को निकलने देते हैं। अगर वॉल्व बंद रहेंगे तो दबाव से कूकर फट जाएगा। मैं अव्यवस्था, अराजकता या क्रांति की जगह व्यंग को प्राथमिकता देता हूं। मुझे यह भी लगता है कि यह हमारा काम है कि भारत के युवाओं की समस्याओं को पहचानें और उनका समाधान करके दें। आइए, बैन हटाएं और जुड़ जाएं!'

स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला : प्रेगाबालिन दवा अब शेड्यूल एच1 में शामिल, दुरुपयोग पर सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के तहत प्रेगाबालिन दवा को शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला कुछ राज्यों से मिली उन रिपोर्टों को देखते हुए लिया गया है, जिनमें प्रेगाबालिन के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग की बात सामने आई थी। नियमों का उल्लंघन करने और उनका पालन नहीं करने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि यह दवा पुराने दर्द, न्यूरोपैथी, फाइब्रोमायल्जिया और कुछ विशेष न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के इलाज के लिए दी जाती है, लेकिन कथित तौर पर इसके नींद लाने वाले, उत्साह पैदा करने वाले और मानसिक प्रभावों के कारण इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रदेश में 10 लाख शस्त्र लाइसेंसधारी, छह हजार से ज्यादा दागी, हाईकोर्ट ने तलब की बाहुबलियों की कुंडली

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि सूबे में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिसमें 6,062 लोग दागी हैं। इस जानकारी से हैरान कोर्ट ने 26 मई तक उन बाहुबलियों, रसूखदारों की आपराधिक कुंडली और उन्हें मिली सरकारी सुरक्षा का ब्योरा तलब किया है, जिनका नाम सरकारी हलफनामे में गुम है। इनमें अब्बास अंसारी, भाजपा नेता बृजभूषण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समेत कई के नाम शामिल हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संतकबीर नगर निवासी जय शंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर दिया है। इससे पहले

गन कल्चर से चिंतित कोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस के आवंटन, नवीनीकरण और नियमों की अनदेखी को लेकर मंडलवार जारी शस्त्र लाइसेंस की जानकारी मांगी थी। इसके क्रम में जो जानकारी अपर मुख्य सचिव (गृह) और संयुक्त सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे में दी गई, उस आंकड़े से कोर्ट हैरान है।

यूपी में 10 लाख से ज्यादा लाइसेंसधारी

हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में मौजूदा समय में 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। अलग-अलग श्रेणियों में 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। 6,062 ऐसे मामले हैं, जहां दो या दो से अधिक आपराधिक मुकदमों वाले व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं। पुलिस प्रमुखों और डीएम के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं।

अधिकारियों की ओर से पेश

कोर्ट की चेतावनी

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है। कहा है कि सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर जानकारी पेश करते वक्त यह लिखित अंडरटेकिंग देंगे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। यदि कोई तथ्य छिपाया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसे कर्तव्य के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही माना जाएगा।

हलफनामे से कोर्ट अभी भी असंतुष्ट है। कोर्ट ने पाया कि अपर मुख्य सचिव (गृह) और संयुक्त सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे में जो आंकड़े सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन कई बार राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों की जानकारी छिपा लेता है। इसलिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने जोन-वार अपराधियों के साथ-साथ कई बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसों की भी जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इन्हें किस श्रेणी की सुरक्षा मिली है, कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं और इनके पास कितने असलहे हैं।

हथियारों के प्रदर्शन से आत्मरक्षा नहीं, भय झलकता है: हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भले ही दबदबा, ताकत और सुरक्षा का भ्रम पैदा करता हो पर यह अक्सर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है। आम जनता में भय व असुरक्षा की भावना पैदा करता है। खुलेआम हथियार लेकर चलना भले ही आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराया जाए, लेकिन जब ये डराने-धमकाने का जरिया बन जाते हैं तो इनसे सुरक्षा नहीं, बल्कि खौफ पैदा होता है। ऐसा समाज जहां हथियारबंद लोग बलपूर्वक अपना दबदबा कायम करते हैं, वह शांतिप्रिय नहीं हो सकता।

कोर्ट ने इनकी मांगी है कुंडली

नोएडा कमिश्नरेट क्षेत्र के अमित कसाना, अनिल भाटी, रणदीप भाटी, मनोज आसे, अनिल दुजाना, सुंदर सिंह भाटी, शिवराज सिंह भाटी। मेरठ जोन के उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, मदन सिंह बद्दो, हाजी याकूब कुरैशी, शारिक, सुनील राठी, धर्मेंद्र, यशपाल तोमर, अमरपाल कालू, अनुज बरखा, विक्रांत विक्की, हाजी इकबाल, विनोद शर्मा, सुनील उर्फ मूंछ, संजीव माहेश्वरी, विनय त्यागी उर्फ टिंकू। आगरा जोन के अनिल चौधरी, ऋषि कुमार शर्मा। बरेली जोन के एजाज। लखनऊ जोन और लखनऊ कमिश्नरेट के खान मुबारक, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, संजय सिंह सिंघाला, अतुल वर्मा, मोहम्मद साहिब, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह, लल्लू यादव, बच्चू यादव, जुगनू वालिया उर्फ हरविंदर।

प्रयागराज जोन और कमिश्नरेट के डब्बू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, बच्चा पासी उर्फ निहाल सिंह, दिलीप मिश्रा, जावेद, राजेश यादव, गणेश यादव, कमरूल हसन, जाविर हुसैन। वाराणसी जोन और कमिश्नरेट के त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह, अखंड प्रताप सिंह, रमेश सिंह काका, अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर, बृजेश कुमार सिंह, सुभाष सिंह ठाकुर, अब्बास अंसारी, पिंटू सिंह। गोरखपुर जोन और कमिश्नरेट के राजन तिवारी, संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी, राकेश यादव, सुधीर सिंह, विनोद उपाध्याय, रिजवान जहीर, देवेंद्र सिंह और कानपुर जोन के अनुपम दुबे और सऊद अख्तर शामिल हैं।

भीषण गर्मी का असर : 15 जून तक बंद रहेंगे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी, प्रचण्ड धूप और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र 20 मई 2026 से 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जा चुका है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय परिसरों में संचालित होते हैं और यहां आने वाले छोटे बच्चे तेज गर्मी और लू से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अवकाश अवधि के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की ड्यूटी पूर्ववत जारी रहेगी। उन्हें लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण, बच्चों का वजन, गृह भ्रमण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन, वीएचएसएनडी सत्र तथा आरबीएसके टीम के साथ बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भन जैसे कार्य नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका केंद्र अथवा मुख्यालय नहीं छोड़ेगी। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के 20 डॉक्टर निलंबित, 3 दिन हड़ताल और बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई, वकीलों का धरना समाप्त

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन हॉस्पिटल) में तीन दिन से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल और बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉक्टर वीके पांडे ने घटना की जांच समिति की संस्तुति के बाद ट्रामा सेंटर के 20 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है।

निलंबित होने वाले डॉक्टरों में 10 जूनियर और शेष सीनियर रेजिडेंट आर्थो विभाग के हैं। बताया गया है महिला वकीलों से मारपीट के दौरान यही डाक्टर ड्यूटी पर तैनात थे। मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर मोहित जैन और जांच समिति के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप चौरसिया ने बताया कि जांच अभी चल रही है। डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। जांच पूरी होने के बाद भी यह देखा जाएगा की किसकी क्या गलती थी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों का धरना-प्रदर्शन समाप्त

वहीं इस कार्रवाई के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उनका धरना-प्रर्दशन समाप्त हो गया। वहीं डॉक्टर अभी काम पर नहीं लौटे हैं और वे अस्पताल परिसर में समूह में खड़े हैं। इस कार्रवाई के बाद डॉक्टर काम पर लौटेंगे या नहीं, इस पर अभी संशय है।

प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार

माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद डॉक्टरों का गुस्सा भड़क भी सकता है। प्रशासन हर स्थिति से निपटने पर विचार कर रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक करने जा रहे हैं।

कुशाग्र राव ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण, एसपी चारू निगम ने किया सम्मानित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। युवा खिलाड़ी कुशाग्र राव ने सीआईएससीई ज़ोनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2026 की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 18 से 20 मई तक लखनऊ पब्लिक कॉलेज, ए-ब्लॉक राजाजीपुरम में आयोजित हुई थी। कुशाग्र ने अंडर-14 वर्ग के 35 से 38 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया। अमीना ताइक्वांडो अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुशाग्र राव को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सीआईएससीई की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान कर सम्मानित किया गया। उनकी इस सफलता से खेल प्रेमियों और अकादमी से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को सुलतानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कुशाग्र राव को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों में अनुशासन, मेहनत और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी हैं। उन्होंने कुशाग्र की प्रतिभा और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी जिले का नाम प्रदेश और देश स्तर पर रोशन करते हैं। एसपी चारू निगम ने कुशाग्र की प्रशिक्षिका अमीना बानो के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे प्रशिक्षकों की मेहनत और सही दिशा-निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सहायक बनती है। अमीना ताइक्वांडो अकादमी के अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर सिंह, कोषाध्यक्ष एडवोकेट मदन सिंह तथा सदस्य कांति सिंह ने भी कुशाग्र राव की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने प्रशिक्षिका अमीना बानो और कुशाग्र के माता-पिता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

नीट-यूजी पेपर लीक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद : अशोक सिंह बिसेन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अशोक सिंह बिसेन ने नीअ-यूजी पेपर लीक मामले को देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और भ्रष्टाचार करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

श्री बिसेन ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी के कारण पिछले 12 वर्षों में देश और प्रदेश में पेपर लीक के लगभग 70 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े गए लोगों के तार भाजपा और संघ से जुड़े लोगों से सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्ट

नेताओं, अधिकारियों और शिक्षा माफियाओं के गठजोड़ ने पूरी परीक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया है। एडवोकेट अशोक सिंह बिसेन ने कहा कि देश का युवा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में भी असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवा आने वाले समय में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को जवाब देंगे।

दिनदहाड़े नाबालिग का अपहरण, गमछे से बंधी हालत में मिली किशोरी

सुल्तानपुर। जिले के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। घटना 20 मई की दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब किशोरी अपने नए घर से पुराने घर की ओर जा रही थी। पीड़िता की मां द्वारा गोसाईंगंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, गांव निवासी सूर्यभान यादव उर्फ अमित पुत्र जन्त्री प्रसाद यादव तथा प्रवेश यादव पुत्र सभा बहादुर यादव कार लेकर रास्ते में खड़े थे। आरोप है कि जैसे ही किशोरी वहां पहुंची, दोनों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आसपास क्षेत्र में तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे बाद किशोरी उसी कार में गमछे से बंधी हालत में मिली। मामले में गोसाईंगंज पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद काटी थी मासूम की गर्दन, पिता-पुत्र समेत 4 कातिलों को उम्रकैद, 3 लाख का जुर्माना

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आठ वर्ष पुराने अपहरण और हत्याकांड में न्यायपालिका ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। अपर जिला जज (सप्तम) चंचल की अदालत ने एक नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को कसूरवार ठहराया है। अदालत ने इन चारों अपराधियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 75-75 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, अपहरण और हत्या का यह पूरा मामला जनपद के मूंढापांडे थाना इलाके का है, जहां मोहम्मद यामीन नामक व्यक्ति के 12 वर्षीय भांजे जीशान का आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी रशीद, उसके पुत्र सुहेल, फैजान और फराज ने अपना जुर्म

कबूल किया था। अपराधियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने मृतक बच्चे का शव बरामद किया था, जिसके बाद अदालत में पुख्ता चार्जशीट दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को बारीकी से परखने के बाद अदालत ने इस खौफनाक हत्या की वारदात के लिए चारों को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया है।

सट्टे का चक्कर और अपहरण की साजिश

मुरादाबाद पुलिस की गहन पड़ताल में यह बात सामने आई कि इस पूरी हिंसक वारदात की मुख्य वजह सट्टे के नंबरों को लेकर चल रहा विवाद था। दरअसल, अपराधी जीशान के मामा यामीन के भाई हाफिज मोबीन के बेटे को बंधक बनाना चाहते थे। मोबीन के साथ आरोपियों की सट्टेबाजी के अंकों को लेकर अनबन चल रही थी। योजना के मुताबिक आरोपी पहले मोबीन के पुत्र को उठाने की ताक में थे, लेकिन जब वह उनके हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने राह चलते 12 साल के मासूम जीशान को अपनी साजिश का शिकार बना लिया। किडनैपिंग के बाद अपराधियों को पुलिस के हत्थे चढ़ने का डर सताने लगा, जिसके कारण उन्होंने बच्चे की जान ले ली।

क्यों पार की थी क्रूरता की हदें

इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की बेरहमी ने समाज और जांच टीम दोनों को झकझोर कर रख दिया था। कानूनी छानबीन में यह सच उजागर हुआ कि मासूम जीशान की हत्या करने के बाद उसकी शिनाख्त मिटाने के उद्देश्य से कातिलों ने उसकी गर्दन को धड़ से काट दिया था। इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने के बाद उन्होंने बच्चे के शरीर के हिस्सों को रामगंगा नदी के तेज बहाव में फेंक दिया था, ताकि अपराध का कोई सुराग न मिल सके।

दो लोगों को क्लीनचिट

शुरुआती दौर में जब जीशान के मामा यामीन ने इस किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, तब उन्होंने सिविल लाइंस इलाके के निवासी मोहम्मद आमीर और मुरसलीन को नामजद करते हुए उन पर शक जताया था। हालांकि, जब पुलिस महकमे ने इस मामले की परतें खोलनी शुरू कीं और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गहन विवेचना की, तो इन दोनों नामजद युवकों की भूमिका पूरी तरह झूठी पाई गई। अपराध में कोई संलिप्तता न मिलने के कारण पुलिस ने इन दोनों को बेकसूर मानते हुए केस से बरी कर दिया था।

ऊंचाहार एनटीपीसी में लगेगी 800 मेगावाट की नई यूनिट, यूपी समेत 9 राज्यों की पूरी होगी बिजली की डिमांड

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। बिजली उत्पादन बढ़ेगा एनटीपीसी में नई यूनिट लगाने तैयारी जारी हो गई है 800 मेगावाट की नई यूनिट लगाई जाने से बिजली की मांग को पूरा करने में आसानी होगी ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना में बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है यहां पर 800 मेगावाट की नई यूनिट लगाई जाएगी उच्च स्तर पर इसके कवायद शुरू हो गई है।

ऊंचाहार परियोजना में यह सबसे बड़ी यूनिट होगी इसके बनने से बिजली की मांग को पूरा करने में आसानी होगी । बिजली की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं इसके लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

एनटीपीसी परियोजना की अभी 1550 मेगावाट क्षमता है। इसकी क्षमता में और वृद्धि की जाएगी। उच्च

स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है यहां 800 मेगावाट की इकाई लगाई जाएगी नई इकाई लगाने के लिए परियोजना में पर्याप्त जगह है।

नई यूनिट लगने के यहां पर सारे पैरामीटर भी दुरुस्त आए नई इकाई लगाने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी इसके लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी इन यूनिट के लगने से बिजली उत्पादन और बढ़ जाएगा लोगों को बेहतर बिजली मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अभी 6 यूनिट कर रही हैं काम

वर्तमान में एनटीपीसी परियोजना में 6 इकाइयां हैं इसमें यूनिट संख्या 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक के उत्पादन क्षमता 210-210 मेगावाट है छठवीं यूनिट का उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। इस परियोजना से 1550 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अब इसकी क्षमता में वृद्धि की तैयारी है।

नौ राज्यों को मिलती है बिजली

ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना में विद्युत आपूर्ति उत्तरी ग्रिड के माध्यम से की जाती है। इस परियोजना में से 9 राज्यों दिल्ली हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को बिजली मिलती है। इन राज्यों में भी बिजली की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। क्षमता बढ़ाने से मांग को काम किया जा सकेगा। ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना के मानव संसाधन विभाग के अपर महाप्रबंधक पंकज कुमार का कहना है कि ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना की क्षमता बढ़ेगी अब जहां भी नहीं यूनिट लगती है। उसकी क्षमता 800 मेगावाट की होती है। यहां भी 800 मेगावाट की यूनिट लगेगी अभी कर योजना प्रारंभिक स्तर पर चल रहा है।

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो बच्चों का नि :शुल्क ऑपरेशन

दोस्तपुर/सुलतानपुर। व्यायु स्वास्थ्य केन्द्र दोस्तपुर में अधीक्षक डॉ अजीत सिंह की अध्यक्षता में संचालित आर.बी.एस.के. टीम द्वारा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो बच्चों की पहचान कर उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। आर.बी.एस.के. टीम में शामिल डॉ रेशमा, डॉ प्रीती सिंह, फार्मासिस्ट विवेक तिवारी एवं फार्मासिस्ट अरविन्द यादव द्वारा बच्चों के परीक्षण के दौरान दोनों बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के लक्षण पाए गए थे। इसके बाद टीम ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया। समय रहते जांच और उपचार मिलने से दोनों बच्चों का सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली। इस अवसर पर अधीक्षक डॉ अजीत सिंह ने कहा कि आर.बी.एस.के. योजना के माध्यम से बच्चों में गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उरई में मायके जाने की जिद में 4 साल की बेटी की ले ली जान, उरई में मां ने घोंट दिया अपनी ममता का गला

आर्यावर्त संवाददाता

उरई। आटा थाना के अकबरपुर इटौरा गांव में मायके जाने को लेकर विनीता का अपने पति और सास से विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने अपनी चार साल की मासूम पुत्री मैना को गला घोट कर मार डाला। विनीता बच्चों को लेकर मायके जालौन जाना चाहती थी, इस कारण वह सास व पति से रुपये मांग रही थी।

पति ने कहा कि अभी मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। पैसा मिलते ही उसे देगा तो मायके चली जाए। इस बार तो लेकर पिछले एक सप्ताह से दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। गुरुवार की रात को कहासुनी ज्यादा बढ़ गई थी। पुलिस ने जांच के बाद विनीता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

ग्राम अकबरपुर इटौरा निवासी राजकुमार मजदूरी करके पत्नी विनीता, पुत्र 12 वर्षीय मयंक, आठ

वर्षीय उमंग व चार वर्षीय पुत्री नैना का भरण पोषण करता था। एक महीने पहले विनीता ने कहा था कि बच्चों को गर्मियों में स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो वह मायके जाना चाहती है। पति ने कहा कि अभी कुछ पैसों की समस्या है कुछ दिन बाद चली जाना इस पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। पत्नी आए दिन मायके जाने की जिद करती और पति उसे मना कर देता था। शुक्रवार की सुबह फिर से पति पत्नी में फिर से झगड़ा हुआ तो विनीता ने कमरे में लेटी चार वर्षीय पुत्री नैना का गला घोट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद विनीता रोने लगी तो पति अंदर पहुंचा देखा नैना मृत पड़ी। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई मां को कोसता नजर आया। थाना प्रभारी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और जांच कर शव को कब्जे में ले लिया। बताया कि मां को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने ₹655 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, बोले- 'हम समस्याएं नहीं समाधान देते हैं'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया जनपद को 655 करोड़ रुपये की 19 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रदेश सरकार की विकास नीति, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा संदेश दिया। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि प्रदेश की जनता लगातार विकास और सुशासन के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। वर्ष 2014 के बाद देश ने नए भारत का दर्शन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए तीव्र गति से बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, उसका लाभ आम जनता तक उतनी ही तेजी से पहुंचेगा।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को निर्देश देते हुए कहा कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और नए शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने की तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, कम लागत और अधिक उत्पादन के तौर-तरीकों से जोड़ने का माध्यम बनेगा, जिससे खेती को नई दिशा मिलेगी।मुख्यमंत्री ने देवरिया के बदले स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब गोरखपुर से देवरिया की यात्रा कठिन मानी जाती थी। सड़कों की स्थिति खराब थी, कई मार्ग एकल लेन के थे और चौरी-चौरा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन आज देवरिया फोर लेन संपर्क मार्गों से जुड़ चुका है और यात्रा का समय काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि देवरिया से बलिया तक सड़क परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। देवरिया-कसया फोर लेन मार्ग और बाईपास बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि यह क्षेत्र उत्तर-दक्षिण संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। यह मार्ग देवरिया को मऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी और लखनऊ से जोड़ने के साथ गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी संपर्क स्थापित करेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास संभव नहीं है। अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत संपर्क व्यवस्था ही निवेश और रोजगार की आधारशिला होते हैं। इसी सोच के साथ देवरिया-कसया मार्ग, बरहज मार्ग, फ्लाईओवर और अन्य पुलों के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि यह विकास यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। देवरिया में बाईपास निर्माण तेजी से चल रहा है और जनता से जुड़े प्रत्येक प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा।

स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक देवरिया में मेडिकल कॉलेज की कल्पना भी कठिन थी, लेकिन आज महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। जल्द ही नए जिला अस्पताल के निर्माण को भी गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार और उद्योगों से जोड़ा जा सके।मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उस समय हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था। त्योहारों के दौरान उपद्रव होते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे और बेटियों व व्यापारियों में भय का माहौल था। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। "वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया" की जगह "वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज" और "वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट" ने ले ली है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अब कोई भी गुंडा या माफिया व्यापारियों से अवैध वसूली का साहस नहीं कर सकता।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ रही हैं और रात्रिकालीन पाली में भी कार्य कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि कोई असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का दुस्साहस करता है, तो कानून उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करता है।किसानों और गरीबों के लिए संचालित योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गन्ने का 400 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचाया जा रहा है और कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब परिवारों को बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन वितरण और उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षकों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में देवरिया की जनता ने भाजपा को सातों सीटों पर विजय दिलाकर विकास की राजनीति पर विश्वास जताया। इसलिए सरकार देवरिया की किसी भी विकास परियोजना को रुकने नहीं देगी। उन्होंने सलेमपुर, तमकुही, बरहज, रुद्रपुर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना समेत सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का

एनआरएलएम योजना में अनुसूचित जनजाति मद हेतु 13 .77 करोड़ रुपये मंजूर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मद में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बड़ी धनराशि जारी की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में शासन ने एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर स्वीकृति के सापेक्ष अनुदान संख्या-81 (अनुसूचित जनजाति मद) के अंतर्गत केन्द्रांश और राज्यांश की कुल 13 करोड़ 77 लाख 56 हजार 700 रुपये की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है।जारी शासनादेश के अनुसार केन्द्रांश की 8 करोड़ 26 लाख 54 हजार रुपये तथा राज्यांश की 5 करोड़ 51 लाख 2 हजार 700 रुपये की राशि को मिलाकर कुल 13.77 करोड़ रुपये आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी गई है। यह धनराशि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से खर्च की जाएगी।शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न किया जाए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से निकासी सुनिश्चित की जाए। साथ ही योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों, शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए ही व्यय किया जाएगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, उनका परीक्षण और सत्यापन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास तथा मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की होगी। इसके अतिरिक्त धनराशि के नियमानुसार उपयोग और निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व भी इन्हीं अधिकारियों को सौंपा गया है।यदि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जहां ब्याज अर्जित होता हो, तो अर्जित ब्याज का नियमानुसार समायोजन अथवा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की होगी। वहीं सामग्री, उपकरण अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद शासन द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया और संबंधित शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धनराशि के आहरण और व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राहुल गांधी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध कथित अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रूद्र दमन सिंह 'बबलू' के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला दहन किया।प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशों के क्रम में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के प्रयोग पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

आजमगढ़ में बिजली मेगा शिविर पहुंचे ऊर्जा मंत्री, बोले— उपभोक्ताओं की हर समस्या का होगा समाधान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को आजमगढ़ के सठियांव में आयोजित बिजली मेगा शिविर का निरीक्षण कर आम उपभोक्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बिजली बिल में गड़बड़ी, आपूर्ति संबंधी समस्याओं और अन्य शिकायतों के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि विभाग जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरी गंभीरता और तत्परता से कार्य कर रहा है।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेगा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बिजली बिल संशोधन, शिकायतों के निस्तारण तथा तकनीकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के चलते इस समय प्रदेश में बिजली की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मांग के कारण कुछ स्थानों पर विद्युत व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन विभाग लगातार व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुटा हुआ है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बढ़ती मांग के अनुरूप प्रदेश में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बिजली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल से लेकर अस्पतालों के उपकरण और दैनिक जीवन की लगभग सभी गतिविधियां बिजली पर निर्भर हैं, इसलिए सरकार विद्युत व्यवस्था को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।ए.के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली से संबंधित हर प्रकार की शिकायत का अधिकारियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा और जनता को राहत पहुंचाने के लिए विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करता रहेगा।

लखनऊ में जनगणना–2027 के प्रथम चरण का शुभारम्भ, 110 वार्डों में शुरू हुआ मकान सूचीकरण अभियान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की नम्बरिंग' का शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में विधिवत शुभारम्भ कर दिया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों और महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार नगर निगम सीमा के सभी 8 जोन एवं 110 वार्डों में यह राष्ट्रीय महत्व का अभियान एक साथ प्रारम्भ हुआ।नगर निगम प्रशासन के अनुसार जनगणना के इस वृहद कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 6270 प्रगणकों और 1049 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि सभी कार्मिकों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विस्तृत प्रशिक्षण देने के बाद क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि आंकड़ों के संकलन में शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान को लेकर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह एवं विनय कुमार राय ने स्वयं अति-विशिष्ट व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आवासों पर पहुंचकर मकान सूचीकरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ कराया। अधिकारियों ने नागरिकों को जनगणना के उद्देश्य समझाते हुए सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया, जिससे लोगों में अभियान के प्रति जागरूकता देखने को मिली।प्रथम दिन प्रगणकों ने अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर भवनों के उपयोग, भवन की प्रकृति, परिवार में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं का संकलन प्रारम्भ किया। नगर निगम के अनुसार नागरिकों द्वारा भी इस कार्य में सकारात्मक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले प्रगणकों को आवश्यक समय दें तथा सही जानकारी उपलब्ध कराकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि "शुद्ध आँकड़े, सशक्त भारत" के संकल्प के साथ लखनऊ नगर निगम निर्धारित समयावधि में जनगणना-2027 के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीबीएयू में 'योग महोत्सव–2026' का शुभारंभ, एक माह तक होंगे योग, ध्यान और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में शुक्रवार को योग विभाग एवं योग वेलनेस सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 'योग महोत्सव–2026' का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में आयोजित यह महोत्सव '12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस–2026' के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, जो आगामी 21 जून 2026 तक एक माह की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा।विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के अंतर्गत 22 मई से 21 जून तक प्रतिदिन प्रातःकाल कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ध्यान सत्र, योग चिकित्सा कार्यशालाएं, मानसिक स्वास्थ्य एवं जीवनशैली संबंधी विकारों पर विशेष व्याख्यान, योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 108 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, योग रैली, जन-जागरूकता अभियान तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए विशेष अभ्यास सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।योग महोत्सव–2026 की विशेषता यह भी है कि इस वर्ष योग विभाग द्वारा बच्चों के लिए 'एक माह का योग ग्रीष्मकालीन शिविर' प्रारंभ किया जा रहा है। इस शिविर में योग के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिल सके।योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिपेश्वर सिंह ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का भी आधार है।

○ संक्षेप ○

महिगवां में अनियंत्रित होकर पलटी टैक्सी, चालक की मौत

लखनऊ। राजधानी के महिगवां थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में टैक्सी चालक की मौत हो गई। बीकेटी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक टैक्सी/विक्रम वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक वाहन के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार को लगभग 3:20 बजे थाना महिगवां क्षेत्र के पहाड़पुर चौराहे पर शिफा क्लिनिक के सामने हुई। बीकेटी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार टैक्सी/विक्रम अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान वाहन चालक साबरीन पुत्र अजीज, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम रायसिंहपुर थाना महिगवां, वाहन के नीचे दब गया। दुर्घटना में उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल चालक को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए 100 शैय्या अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

भीषण गर्मी में बिजली संकट पर मायावती की चिंता, सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की अपील

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति में कमी और कटौती को लेकर प्रदेश सरकार पर चिंता जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिजली संकट के कारण गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों और मेहनतकश लोगों का जीवन अत्यधिक कष्टदायी बन गया है।मायावती ने शुक्रवार को सामाजिक माध्यम 'एक्स' पर जारी अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में गर्मी के मौसम के दौरान कम बिजली आपूर्ति और बार-बार कटौती की शिकायतें आम हो गई हैं। इसे लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं और इस विषय की चर्चा लगातार मीडिया में भी हो रही है।बसपा प्रमुख ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जनता की परेशानियों और कष्टों को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम तत्काल सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में बिजली संकट से निपटने के लिए नए पावर प्लांटों की स्थापना और ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।मायावती ने कहा कि बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार व्यापक जनहित में होगा और इससे प्रदेश के करोड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी।

कालाबाजारी, घटतौली और राशन घोटाले पर सख्त हुए मंत्री मनोज पांडेय, बोले— गरीबों का हक मारने वालों को भेजेंगे जेल

लखनऊ, (आरएनएस)। खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और गरीबों के अधिकारों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वाले, तौल में चोरी करने वाले और सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि गरीबों और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, शिकायतों की अनदेखी अथवा दोषियों को संरक्षण देने की बात सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बीकेटी के तेजस हॉस्पिटल में महिला मरीज से दुष्कर्म का आरोप, चिकित्सक गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बक्शी का तालाब (बीकेटी) क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के साथ दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अस्पताल संचालक एवं चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।पुलिस के अनुसार 21 मई को थाना बक्शी का तालाब क्षेत्र के इन्दौराबाग स्थित तेजस हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ अस्पताल संचालक द्वारा उपचार के दौरान अनुचित कृत्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की गई।पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बीकेटी में मुकदमा संख्या 189/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(e) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद आरोपी विजय कुमार गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से ग्राम रजनापुर, थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर का निवासी बताया गया है और वर्तमान में बीकेटी के इन्दौराबाग क्षेत्र में किराये के भवन में तेजस हॉस्पिटल संचालित कर रहा था।पुलिस के अनुसार पीड़िता को 19 मई 2026 को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उपचार के दौरान 21 मई को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर कक्ष में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वाहनों में निगरानी यंत्र लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव, यात्रियों की सुरक्षा होगी और मजबूत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में यात्रा को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निगरानी आधारित बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थिति निगरानी यंत्र लगाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शासन ने एक जनवरी 2019 से पहले और बाद में पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए अधिकृत कंपनियों, यंत्रों और वाहन निर्माताओं के दायरे में विस्तार, संशोधन तथा कुछ मामलों में विलोपन का निर्णय लिया है, जिससे वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों को सुविधा मिल सके।यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थिति निगरानी यंत्र लगाने और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए शासन स्तर पर व्यापक निर्णय लिए गए हैं। नए निर्माताओं और यंत्र मॉडलों को मंजूरी देने के साथ पहले से स्वीकृत कंपनियों के दायरे में विस्तार और संशोधन भी किया गया है।परिवहन मंत्री ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कई नई कंपनियों को अधिकृत किया गया है। इनमें पीएसडीएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की निगरानी यंत्र प्रणाली को स्टेलेंटिस कंपनी के वाहनों में लगाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार एक्यूट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की यंत्र प्रणाली को पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के वाहनों में स्वीकृति प्रदान की गई है। एपीएम समूह प्राइवेट लिमिटेड तथा एपीएम किंग्सट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी पीएमआई कंपनी के वाहनों में यंत्र लगाने की अनुमति दी गई है।सरकार ने वाहन स्वामियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पहले से स्वीकृत कंपनियों के दायरे का भी विस्तार किया है। रोजमर्टा ऑटोटेक लिमिटेड की निगरानी यंत्र प्रणाली को पहले महिंद्रा और रेनो वाहनों के लिए अनुमति थी, जिसे अब होंडा, टोयोटा तथा एमजी मोटर्स के कुछ प्रमुख मॉडलों तक विस्तारित कर दिया गया है। इसी प्रकार ब्लैकबॉक्स जीपीएस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और वाटसू एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को भी अतिरिक्त वाहन निर्माताओं के वाहनों में यंत्र लगाने की अनुमति दी गई है। परिवहन विभाग ने अभिलेखों में संशोधन करते हुए कुछ कंपनियों के नाम और वाहन निर्माताओं के दायरे में भी परिवर्तन किया है, ताकि भविष्य में वाहन स्वामियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और यंत्र लगाने की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके।वहीं, वाहन निर्माता हुंडई द्वारा अधिकृत पत्र निरस्त किए जाने के बाद शासन ने रोजमर्टा ऑटोटेक लिमिटेड को दी गई अनुमति से हुंडई कंपनी के वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। ऐसे वाहन स्वामियों को अब अन्य अधिकृत विकल्पों के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी।परिवहन मंत्री ने बताया कि एक जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत पुराने सार्वजनिक सेवा वाहनों में भी निगरानी यंत्र लगाने और सक्रिय करने के लिए तीन अतिरिक्त कंपनियों को पात्र मानते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पुराने वाहनों के स्वामियों को भी आसानी से निर्धारित मानकों के अनुरूप यंत्र लगवाने की सुविधा मिल सकेगी। दयाशंकर सिंह ने प्रदेश के सभी सार्वजनिक सेवा वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्माता के अनुरूप अधिकृत कंपनियों से ही संपर्क कर समय से वाहन स्थिति निगरानी यंत्र का फिटमेंट और सक्रियण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं।

घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं?

मुंबई के लिए मुसीबत बने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस और प्रशासन ने करारा सबक सिखाकर देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी राहत दिलाई है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान न केवल रेलवे भूमि को मुक्त कराने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ, बल्कि इस कार्रवाई ने यह भी उजागर कर दिया कि किस तरह अवैध कब्जाधारी कानून व्यवस्था को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेलवे अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि देश के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण हटाने या अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलते ही इन घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के निकट गरीब नगर में फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। यह मुंबई में रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई मानी जा रही है। रेलवे के अनुसार लगभग पांच हजार दो सौ वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब छह सौ करोड़ रुपये आंकी गई है। यह इलाका हार्बर लाइन की पटरियों और बिजली व्यवस्था के बेहद करीब पहुंच चुका था, जिससे रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला झुग्गियां फुटओवर पुलों की ऊंचाई से भी ऊपर तक बना दी गई थीं। इससे भविष्य की रेलवे परियोजनाओं और ट्रेनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रेलवे लंबे समय से इस भूमि को खाली कराना चाहता था, क्योंकि बांद्रा स्टेशन और बांद्रा कुर्ला परिसर के पास स्थित यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया वर्ष 2017 से पहले शुरू हो चुकी थी। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 27 नवंबर 2017 को बेदखली आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद मामला बंबई उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इस वर्ष 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। पश्चिम रेलवे ने करीब पांच सौ झुग्गियों को हटाने के लिए चिन्हित किया, जबकि संयुक्त सर्वेक्षण में पात्र पाए गए लगभग एक सौ ढांचों को फिलहाल नहीं छुआ गया। रेलवे का कहना है कि भविष्य में इस जमीन का उपयोग उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। करीब चार सौ पुलिसकर्मी, चार सौ रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के जवान तथा लगभग दो सौ रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। बांद्रा स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के आसपास कई रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे भारी यातायात जाम लग गया और यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलना पड़ा। शुरुआत में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन दोपहर बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों ने जब एक अवैध मस्जिद और वहां लगाए गए निजी दूरसंचार टावर को हटाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने दस लोगों को हिरासत में लिया और निर्मल नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। घायलों का उपचार भाभा अस्पताल और वीएन देसाई अस्पताल में कराया गया। एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, हालांकि दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कुछ निवासियों ने दावा किया कि वह कई दशकों से यहां रह रहे थे और उनके पास हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईद से ठीक पहले की गई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि इन दावों और मानवीय पक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अवैध कब्जों के खिलाफ हर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? चाहे देश का कोई भी राज्य हो, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन पर हमला करना अब एक तयशुदा रणनीति जैसा दिखाई देता है। इससे साफ है कि कुछ तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़कर सरकारी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं।

बस्तर में बैंकिंग क्रांति - विश्वास, विकास और बदलाव की नई इबारत

दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लेकर आ रही है। पहले लोगों को छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय या अन्य कस्बों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।

सुनील त्रिपाठी,

एक समय नक्सल हिंसा और विकास की चुनौतियों के लिए पहचाने जाने वाला बस्तर अब बदल चुका है। आज बस्तर शांति, विश्वास, सुशासन और विकास की नई पहचान बन रहा है। नक्सलमुक्त होते बस्तर में अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विस्तार पा रही हैं। कभी बैंकिंग सुविधाओं के अभाव, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित वित्तीय पहुंच के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग में अब परिवर्तन की नई कहानी लिखी जा रही है। इसी परिवर्तन का सबसे मजबूत उदाहरण है पिछले ढाई वर्षों में बस्तर संभाग में 31 नई बैंक शाखाओं का खुलना। श्री विष्णु देव साय की सरकार के गठन के बाद बस्तर में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिली है। दूरस्थ और पूर्व में प्रभावित रहे क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच ने यह साबित किया है कि अब बस्तर विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह नया बस्तर है, जहां बंदूक की आवाज नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और समृद्धि की नई गूंज सुनाई दे रही है।

दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लेकर आ रही है। पहले लोगों को छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय या अन्य कस्बों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई गांवों के लोगों को पूरा दिन खर्च कर बैंक पहुंचना पड़ता था। अब गांवों और ब्लॉक स्तर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने से न केवल समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि लोगों का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ाव भी बढ़ रहा है, इससे शासन की योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंच रहा है और पारदर्शिता मजबूत हुई है।

बस्तर संभाग के गांवों और कस्बों में बैंक शाखाओं का खुलना केवल वित्तीय संस्थाओं का विस्तार नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश का प्रतीक है। जिन क्षेत्रों में कभी मूलभूत सेवाएं पहुंचाना चुनौती माना जाता था, वहां आज आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। पिछले ढाई वर्षों में बस्तर संभाग में 31 नई बैंक शाखाएं शुरू हुई हैं, इनमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है। तर्रेम, जगरगुंडा, चिंतलनार, किस्टाराम, पामेड़, समलवार और कोहकामेटा जैसे क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का खुलना विकास और विश्वास दोनों का प्रतीक बन गया है।

बस्तर में शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने के साथ अब विकास कार्यों को नई गति मिली है। बैंक शाखाओं का विस्तार यह दर्शाता है कि अब शासन और जनता के बीच विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ है। जहां कभी लोगों को बैंकिंग कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं अब गांवों और ब्लॉक स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे आम नागरिकों का जीवन आसान हुआ है और वे औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से तेजी से जुड़ रहे हैं। आज बस्तर के ग्रामीण बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, किसान कृषि ऋण, बीमा, पेंशन और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ आसानी से ले पा रहे हैं, इससे आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ी हैं।

बस्तर संभाग की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार से आदिवासी परिवारों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे योजनाओं को लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते में (डी बीटी के माध्यम) मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, तेंदूपत्ता बोनस, वन धन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शी व्यवस्था मजबूत हुई है। महिला स्व-सहायता समूहों को भी बैंकिंग सुविधाओं से बड़ी लाभ मिली है। समूहों को ऋण सुविधा मिलने से आजीविका गतिविधियों और छोटे उद्यमों को नई गति मिली है।

31 नई बैंक शाखाओं के खुलने से बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आधार मिला है। अब छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं को वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी आधारित व्यवस्था की जगह डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम और आधार आधारित भुगतान जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंच चुकी हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक संगठित और पारदर्शी बन रही है। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से बाजार गतिविधियां बढ़ी हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।

बस्तर में बैंकिंग नेटवर्क मजबूत होने से युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़े हैं। बैंक ऋण और वित्तीय सहायता मिलने से युवा अब कृषि आधारित उद्योग, लघु व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप गतिविधियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक मित्र और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। इससे आर्थिक गतिविधियों में स्थानीय स्तर पर नई ऊर्जा दिखाई दे रही है।

बस्तर में बैंकिंग विस्तार यह दर्शाता है कि अब यह क्षेत्र केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि विकास और संभावनाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और बैंकिंग जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार यह साबित कर रहा है कि नक्सलमुक्त बस्तर अब आत्मनिर्भरता और समग्र विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 31 नई बैंक शाखाओं का खुलना केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की नई तस्वीर है- जहां विश्वास है, अवसर हैं और विकास की नई संभावनाएं हैं।

आज बस्तर बदल रहा है। गांवों तक पहुंचती बैंकिंग सेवाएं यह संदेश दे रही हैं कि अब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नक्सलमुक्त बस्तर में मजबूत होता बैंकिंग नेटवर्क आने वाले समय में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है।

लेखक सहायक संचालकजनसंपर्क संचालनालय हैं)

टिप्पणी

शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए

रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह ने अपने चंद दिनों के शासनकाल में नेपाल को अशांत कर दिया है। पूर्व सरकारों के खिलाफ भड़के असंतोष के कारण उल्का की तरह उगे शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए हैं।

बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बने, अभी एक महीना नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच उनकी सरकार ने अलग- अलग जन समूहों में विरोध भड़का दिया है। वित्तीय गड़बड़ी के इल्जाम के कारण गृह मंत्री सुधन गुरुंग को इस्तीफा देना पड़ा। गुरुंग पिछले सितंबर में हुए हुए कथित जेन-जेड विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। उनकी इसी भूमिका के कारण तजुर्बा ना होने के बावजूद उन्हें गृह मंत्रालय जैसा महत्त्वपूर्ण मंत्रालय मिला। मगर सिर्फ 26 दिन बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 27 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद शाह सरकार से हटने वाले वे दूसरे मंत्री हैं। इसके पहले श्रम मंत्री दीपक शाह को भी वित्तीय गड़बड़ी के इल्जाम के कारण ही पद छोड़ना पड़ा था।

इस बीच शाह सरकार के कई फैसलों से नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की कड़ी लग गई है। शाह ने अपने आरंभिक कदमों में सियासी पार्टियों से जुड़े छात्र संघों को भंग कर दिया। इससे छात्र नाराज हो गए। फिर फैसला लिया कि भारत से 100 नेपाली रुपये से अधिक का सामान लाने पर सीमा शुल्क चुकाना होगा। इससे भारतीय सीमा से जुड़े मधेस इलाके में विरोध भड़क उठा। शाह ने जो कदम सबसे पहले उठाया, वह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी था। मगर सरकार उनके खिलाफ साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, जिस कारण कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया।

इससे ओली समर्थकों को सड़कों पर उतरने का मौका मिला। फिर शाह ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और यहां तक कि पूर्व राजा की संपत्ति की जांच कराने का फैसला भी किया है। इससे आरोप लगा है कि बुनियादी समस्याओं का हल तलाशने के बजाय शाह बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो कुल मिला कर रैपर से राजनेता बने शाह ने अपने चंद दिनों के शासनकाल में नेपाल को अशांत एवं अस्थिर कर रखा है। पूर्व सरकारों की अकुशलता, कथित भ्रष्टाचार, और भाई-भतीजावाद से भड़के असंतोष के कारण उल्का की तरह उगे शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए। नतीजा, तेजी से उनकी चमक का उड़ जाना है।

ब्लॉग

इटली और भारत: इंडो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक साझेदारी

नरेंद्र मोदी, औरजॉर्जिया मेलोनी

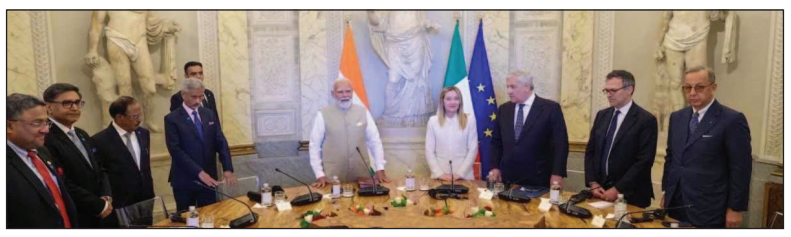

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक—जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है—को भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तथा 2 लाख स्टार्ट-अप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह केवल दो व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। मेड इन इटली हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, और आज इसका स्वाभाविक तालमेल मेक इन इंडिया पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी — जो अब दोनों पक्षों से मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है — एक सकारात्मक संकेत है। यह हमारी सप्लाई चेन के एकीकरण को और मजबूत करेगी।

तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेज़ी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या, तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता—इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों, के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआई का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो।

भारत और इटली एआई को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीकों के जरिए एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है, न कि उन्हें और बढ़ा सकता भारत के मानव विज़न- यानी तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित एल्गोर-एथिक्स की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बने।

हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।

सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआई को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।

आज की तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर आधारित है।

हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीकों के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक, तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है।इस संदर्भ में भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है।

भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों-इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हम एक नए इंडो-मैडिटेरेनियन क्षेत्र के उभरने को देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। इसी आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है।

इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत और इटली अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं वसुधैव कुटुंबकम्-अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है।

ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

लेखक भारत के प्रधानमंत्री, इटली गणराज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष हैं।

कश्मीर से लाया गया हमजा, शुद्धिकरण कराकर फिर से बना विशाल, प्रेमिका की खातिर बदला था धर्म

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर. कश्मीर में धर्म बदलकर हमजा बने विशाल की वापसी हो चुकी है। मंत्रोच्चार के बीच गंगाजल से विशाल का शुद्धिकरण कराया गया। विशाल की घर वापसी होने पर गांव में उत्सव का माहौल रहा। उधर, पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले वसीम को गिरफ्तार कर लिया है।

बृहस्पतिवार को भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी की अगुवाई में तमाम भाजपाई आवास विकास पुलिस चौकी पहुंचे और विशाल सुपुर्दगी में लिया। जिसके बाद विशाल अपने माता-पिता के साथ गांव खानजहांपुर बहादर पहुंचा। जहां ढोल नगाड़ों के साथ विशाल का स्वागत किया गया। गांव के मंदिर पर पंडितों ने गंगाजल से मंत्रोच्चार के साथ विशाल को स्नान कराया। साथ ही पूजा-अर्चना भी की। भाजपा नेता

ऐश्वर्य मौसम चौधरी अपने समर्थकों के साथ गांव में हुए उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। शुद्धिकरण कराने के साथ ही हमजा बने विशाल की फिर से हिंदू धर्म में वापसी हो गई।

छह दिन पहले अपनाया था मुस्लिम धर्म

गांव खानजहांपुर बहादर के कृष्ण कुमार का बेटा तीन साल से कश्मीर में रहकर सैलून का काम करता था। कुपवाड़ा में 15 मई को विशाल ने गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद में कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसी मस्जिद से विशाल को नया नाम मोहम्मद हमजा भी मिला। धर्म बदलने की प्रक्रिया और कलमा पढ़ने की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने उसके मां-बाप के साथ वीडियो कॉल पर बात कर विशाल से वापस आने को कहा था।

धर्म बदलवाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार

बेटे के धर्म बदलने की खबर लगते ही सोमवार को कृष्ण कुमार ने भारतेंद्र सिंह के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत थी। उसी दिन प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस की दो टीमों को कश्मीर भेजा गया। जहां से पुलिस विशाल और आरोपी वसीम को अपने साथ ले आई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी वसीम निवासी काजीवाला बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया है।

हमजा बनकर पूरा होना था निकाह का वादा

भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने बताया कि विशाल से कई सवाल पूछे गए। विशाल ने बताया कि पिछले दो साल से आरोपी की बेटी से वह मोहब्बत करता था। विशाल और उसकी प्रेमिका दोनों निकाह भी करना चाहते थे, मगर प्रेमिका का पिता राजी नहीं हुआ। बाद में प्रेमिका के पिता ने धर्म बदलने की शर्त रख दी, जिसके चलते ही विशाल हमजा बन गया। मगर छह दिन में ही उसकी हिंदू धर्म में वापसी हो गई।

विशाल को समझाया गया : ऐश्वर्य मौसम

भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने बताया कि जिस दिन से पता चला कि विशाल का धर्म परिवर्तन करा दिया है, वह पुलिस और उसके परिवार के संपर्क में रहे। उसे वापस लाने के पूरे प्रयास किए। शुरुआत में वह इन्कार कर रहा था, लेकिन बाद में उसे समझाया गया और आखिर उसे वापस लाने और घर वापसी कराने में सफल रहे।

शादी का दिया था प्रलोभन : एसपी

एसपी अभिषेक झा के अनुसार आरोपी वसीम ने विशाल को इस्लाम धर्म कबूल करने पर बेटी से शादी कराने का प्रलोभन दिया था। विशाल नाबालिग है, जिसे तलाश कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

विकास खंडों में वर्षों से जमे अकाउंटेंटों पर सवाल, तबादला नीति बनी मजाक

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जिले के विकास खंडों में वर्षों से जमे अकाउंटेंटों को लेकर अब विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शासन की तबादला नीति और पारदर्शिता व्यवस्था पर बड़े प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ कर्मचारियों के पास एक-दो नहीं बल्कि दो-दो और तीन-तीन ब्लॉकों का अतिरिक्त चार्ज वर्षों से बना हुआ है।

सूत्रों के अनुसार सत्य नारायण गौतम पिछले लगभग पांच वर्षों से बल्दीराय, चार वर्षों से कुड़वार और दो वर्षों से दूबेपुर विकास खंड का लेखा-जोखा संभाल रहे हैं। वहीं वीर सिंह भारती जयसिंहपुर और कूरेभार में करीब चार-चार वर्षों से तैनात बताए जा रहे हैं। इसी तरह अखंडनगर और कादीपुर विकास खंड में जीतू राम पिछले पांच वर्षों से जमे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अकाउंटेंट जैसे संवेदनशील पद पर एक ही कर्मचारियों को वर्षों तक क्यों बनाए रखा गया? क्या जिले में अन्य कर्मचारियों की कमी है या फिर विभागीय संरक्षण के चलते यह व्यवस्था चल रही है। जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से वित्तीय अनियमितताओं और सांठगांठ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कई ब्लॉकों का अतिरिक्त चार्ज देना विभागीय पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। चर्चा यह भी है कि यदि इन कर्मचारियों के कार्यकाल और वित्तीय अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि तबादला नीति केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है।

मासूम की सांसें बचाने को खाकी बनी फरिश्ता, इंस्पेक्टर ने किया रक्तदान

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। थाना कल्यानपुर क्षेत्र के ग्राम पिलखिनी में बीते सत्रह मई को सिलेंडर लीकेज से लगी भीषण आग की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। हादसे में नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया, वह अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी शुरू कराई। सभी घायलों को तत्काल अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने बिना देर किए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कराया,

जिससे सभी को तेजी से केजीएमयू लखनऊ रेफर किया जा सका। इस त्वरित कार्रवाई से कई घायलों को समय रहते बेहतर उपचार मिल सका। इलाज के दौरान हादसे में झुलसी संगीता की मौत हो गई, लेकिन इसी बीच उनके चार माह के मासूम बेटे बलवंत के इलाज के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे संवेदनशील समय में फतेहपुर पुलिस ने केवल अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक सुनील कुमार ने चिकित्सकों और परिजनों से समन्वय बनाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। समय पर रक्त उपलब्ध होने से मासूम के उपचार में बड़ी मदद मिली। इंस्पेक्टर के इस मानवीय कदम की चिकित्सकों, परिजनों और आम लोगों ने खुलकर सराहना की। पुलिस की इस कार्यशैली ने यह साबित कर दिया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत के समय समाज के साथ खड़ी रहने का भी काम कर रही है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का संदेश इस घटना में पूरी तरह जीवंत दिखाई दिया।

एएन जन सेवा केंद्र का सभासद ने किया शुभारंभ

फतेहपुर। शहर के आबूनगर स्थित पंचमुखी मंदिर के पास को एएन जनसेवा केंद्र का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के सभासद शादाब अहमद ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी में केंद्र संचालक अयाज खान ने लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। संचालक अयाज खान ने बताया कि जन सेवा केंद्र पर फोटो, फोटोकॉपी, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न दस्तावेजों का निर्माण एवं संशोधन सहित कई जरूरी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय लोगों को अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान मोहम्मद हबीब, कृष्ण पाल, मोहम्मद शमशाद, जितेंद्र कुमार तिवारी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद सलीम, फरहान शेख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने नए जन सेवा केंद्र के शुभारंभ पर खुशी जताई और इसे क्षेत्र के लिए उपयोगी पहल बताया।

डायरिया से सुरक्षित रहने को बरतें जरूरी सावधानी

हलिया ब्लाक की 206 आशा कार्यकर्ताओं व 44 एएनएम को किया प्रशिक्षित

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। स्वास्थ्य विभाग जनपद में डायरिया नियंत्रण और रोकथाम को लेकर बेहद गंभीर है। डायरिया के लिहाज से संवेदनशील हलिया ब्लाक की 206 आशा कार्यकर्ताओं, 44 एएनएम और 10 आशा संगिनी को विशेष तौर पर डायरिया की शीघ्र पहचान और जरूरी प्राथमिक उपचार के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू (KENVUE) के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया के सभागार में इन्हें पांच सत्रों (बैच) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं को बताया गया कि वह क्षेत्र में डायरिया से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को पीने के पानी की स्वच्छता के बारे में जरूर बताएं क्योंकि डायरिया का एक प्रमुख कारण दूषित पानी का सेवन भी है।

इस दौरान मुख्य प्रशिक्षक प्रभारी

चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी में डायरिया व अन्य संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। घर व आस-पास साफ़-सफाई रखने के साथ ही स्वच्छ पेयजल का ही इस्तेमाल करें। पानी को उबालकर छानकर और ठंडा होने पर ही पिएं। हाथों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को इस बारे में अन्य जरूरी उपाय भी बताये और कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस बारे में अवश्य बताएं। समुदाय को यह भी बताएं कि वह आकस्मिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए 102 या 108 को डायल कर सकते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर को डायरिया की रोकथाम और उसके इलाज में पहले से मौजूद बेहतरीन तरीकों की पहचान करना और उन्हें दस्तावेज़ के रूप में दर्ज करना आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। उनसे अपेक्षा की गयी वह इन तरीकों को शहरी और ग्रामीण इलाकों के उन हिस्सों तक पहुँचाने पर ज़ोर दें, जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। डायरिया की शीघ्र पहचान के साथ ही जरूरी परामर्श और इलाज के तय प्रोटोकाल आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।

डायरिया के प्राथमिक उपचार के तौर पर पानी जैसी पतली दस्त होने पर ओआरएस का घोल और जिंक की सही खुराक लेने के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया और क्षेत्र में टीकाकरण के महत्व पर ज़ोर दिया गया। क्षेत्र के डायरिया प्रभावित और अति कुपोषित बच्चों का रिकार्ड रखने के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। अन्य प्रशिक्षकों में एआरओ राजकुमार, बीसीपीएम अनिल कुमार, पीएसआई इंडिया से विष्णु प्रकाश आदि शामिल रहे। प्रशिक्षण के दौरान पीएसआई से अर्चना मिश्रा, अन्य संस्थाओं से गुमान सिंह, अंकित शुक्ला आदि का विशेष सहयोग रहा।

जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी जिम्मेदारी: अभिमन्यु

फतेहपुर। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक अचानक चांदपुर थाने पहुंचे। जहां उन्होंने जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। एसपी के थाने पहुंचते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई और फरियादी भी अपनी शिकायतें लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान जमीन विवाद, मारपीट, पारिवारिक कलह और अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें सामने आईं, जिन पर एसपी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल एवं निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फरियादियों को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही या हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'अब समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा...' ममेरे भाई संग 25 लाख के जेवर लेकर भागी बेटी, सदमे में पिता ने खाया जहर

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 22 वर्षीय युवती समाज और परिवार के खिलाफ जाकर अपने ही रिश्ते के ममेरे भाई के साथ घर से फरार हो गई। बेटी के घर से इस तरह भागने की घटना को पिता सह नहीं पाए और जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती के घर से भागने की घटना 14 मई की बताई जा रही है, जब युवती अपने साथ घर में रखे लगभग 25 लाख रुपये के कीमती जेवरात भी समेट ले गई।

मामला जिले के मझोला थाना इलाके का है। इस घटना के बाद से ही युवती का परिवार गहरे मानसिक आघात और सामाजिक बदनामी के डर से जूझ रहा था। विशेष रूप से लड़की के पिता, जो पेशे से एक मजदूर थे, इस अप्रत्याशित कदम से पूरी तरह टूट चुके थे। परिवार द्वारा समाज में अपनी इज्जत खोने का गम

पिता के आत्मसम्मान पर इतनी गहरी चोट कर गया कि उन्होंने अंततः एक आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तमाम कोशिशों और ढांढस बंधाने के बावजूद, वह खुद को इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर नहीं निकाल सके और समाज का सामना न कर पाने की लाचारी में लड़की के पिता ने संदिग्ध जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे मोहल्ले और पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है। रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, युवती के लापता होने के तुरंत बाद परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की थी और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत भी बुलाई गई थी। जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो 15 मई को पुलिस में इस घटना की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी। इसी बीच, एक स्थानीय अधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन को फोन पर सूचित किया कि दोनों प्रेमियों ने पहले ही कोर्ट मैरिज (न्यायालयीन विवाह) कर ली है और वे जल्द ही थाने में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इस कानूनी विवाह की बात सुनते ही पिता का बचा-खुचा संबल भी पूरी तरह टूट गया था। उन्होंने लोकलाज और लोकनिंदा के डर से खुद को कमरे में बंद कर लिया था।

ग्लानि में मजबूर पिता ने खाया जहर

तमाम कोशिशों के बाद भी जब सात दिनों तक बेटी का कोई सुराग नहीं मिला, तो समाज को मुंह न दिखा पाने की ग्लानि में डूबे पिता ने दोपहर करीब दो बजे चुपके से जहर खा लिया। परिजनों को जैसे ही उनकी हालत बिगड़ने का अहसास हुआ, घर में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची मझोला पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान शाम में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद अंत के बाद पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी से प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और तथ्यों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यूपी-112 को मिली स्कॉर्पियो की रफ्तार, अपराधियों की खैर नहीं

फतेहपुर। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पुलिस विभाग को बड़ी सौगात मिली है। यूपी-112 आपातकालीन सेवा के लिए जनपद को पांच नए चार पहिया स्कॉर्पियो वाहन उपलब्ध कराए गए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी ने कहा कि इन आधुनिक वाहनों के संचालन से आपातकालीन घटनाओं में पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम और तेज होगा, जिससे आमजन को त्वरित एवं प्रभावी सहायता मिल सकेगी। नए स्कॉर्पियो वाहनों को थाना गाजीपुर, कल्यानपुर, हथगांव, सुल्तानपुर घोष और खखरेरू क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इन इलाकों में अब यूपी-112 की टीम पहले से अधिक तेजी के साथ घटनास्थल तक पहुंचेगी, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बागवानी विकास को नई दिशा देगा फतेहपुर

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित औद्यानिक योजनाओं की समीक्षा एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना 2026-27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु जिला मिशन समिति (डीएमसी) की बैठक आयोजित की गई।.बैठक में जिला उद्यान अधिकारी डॉ. रमेश पाठक ने जनपद में औद्यानिक फसलों की स्थिति, महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं योजनाओं की प्रगति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने एकीकृत बागवानी मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, एससीपी राज्य सेक्टर तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत गत वर्ष की उपलब्धियों एवं वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित लक्ष्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने जनपद में टिश्यू कल्चर केला, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी आधुनिक फसलों के क्लस्टर विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत केला, आलू, प्याज और मिर्च के प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कराने की दिशा में तेजी लाने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर दिया गया।

पालतू कपिला और तुंगा ने जंगली हाथियों को बनाया दोस्त, उनके साथ उत्तराखंड से यूपी भागीं, दो दिन बाद याद आया घर तो लौटीं

बिजनौर। कार्बेट टाइगर रिजर्व से राहत भरी खबर सामने आई है। जंगली हाथियों के साथ लापता हुईं वन विभाग की पालतू हथनियां कपिला और तुंगा सुरक्षित वापस लौट आई हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना जोन से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह बेहद राहत भरी खबर है।

पिछले दो दिनों से लापता वन विभाग की दो बेहद समझदार और प्रशिक्षित हथनियां, कपिला और तुंगा सुरक्षित अपने कैंप में वापस लौट आई हैं। इनके लौटने से पिछले 48 घंटों से तनाव में चल रहे वन प्रशासन ने आखिरकार चैन की सांस ली है।

जंगली झुंड के साथ निकल गई थीं हथनियां

मामला बिजनौर की अमानगढ़ टाइगर रिजर्व सीमा से सटे कॉर्बेट के झिरना जोन का है। 19 मई की शाम

को वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा रहीं कपिला और तुंगा को रोजाना की तरह जंगल में घास चरने के लिए छोड़ा गया था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे जंगली नर हाथियों के एक झुंड को देखकर दोनों हथनियां उनकी तरफ आकर्षित हो गईं और घास चरते-चरते अचानक उसी झुंड के साथ घने जंगलों में ओझल हो गईं।

वन विभाग की सांसें फूलीं

गश्त दल की रीढ़ मानी जाने वाली इन दोनों हथनियों के अचानक गायब होने से वन अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। कॉर्बेट प्रशासन ने आनन-फानन में कपिला और तुंगा की खोजबीन के लिए वनकर्मियों की कई टीमें गठित कीं। घने जंगलों और जंगली हाथियों के मूवमेंट के बीच रात-दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी टीमों को कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। विभाग की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी।

देर रात खुद ही कैंप वापस लौटीं

जब वन विभाग की टीमें भारी तनाव में थीं, तभी 20 और 21 मई की दरमियानी रात को एक चमत्कार हुआ। घने अंधेरे के बीच कपिला और तुंगा चुपचाप खुद ही चलकर अपने पुराने कैंप में वापस लौट आईं। कैंप के कर्मचारियों ने जैसे ही दोनों को सुरक्षित देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिससे महकमे ने बड़ी राहत महसूस की।

2016 से पेट्रोलिंग बेड़े की शान हैं कपिला और तुंगा

वन अधिकारियों के मुताबिक, कपिला और तुंगा बेहद समझदार, शांत और इंसानी निर्देशों का पालन करने वाली हथनियां हैं। साल 2016 में वन विभाग ने इन्हें कड़ा प्रशिक्षण देकर अपने पेट्रोलिंग बेड़े में शामिल किया था। तब से लेकर आज तक दोनों ने कठिन और दुर्गम रास्तों पर वन्यजीवों की सुरक्षा और तस्करों पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाई है।

अधिकारियों का मानना है कि जंगली हाथियों के झुंड के साथ जाने के बाद भी उनकी पुरानी ट्रेनिंग और कैंप के प्रति वफादारी भारी पड़ी, जिसके चलते वे खुद ही सुरक्षित रास्ते से वापस आ गईं। फिलहाल दोनों हथनियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं।

जन-संवाद से समाधान बना फरियादियों की उम्मीद

» डीएम की नई प्रशासनिक व्यवस्था ने पैदा की हलचल

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अभिनव पहल जन-संवाद से समाधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में नई हलचल पैदा कर दी है। अब फरियादियों को दफ्तर-दफ्तर भटकने के बजाए सीधे जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखने का मौका मिल रहा है, जबकि अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तत्काल जवाब देना पड़ रहा है।

कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान डीएम अपने सामने लैपटॉप रखकर तहसील, ब्लॉक और जनपद स्तरीय अधिकारियों को वीसी से जोड़ रही हैं। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं और मौके पर निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है। इस व्यवस्था से वर्षों से शिकायत लेकर भटक रहे लोगों में उम्मीद जगी है। डीएम की इस सख्त और पारदर्शी कार्यशैली से लापरवाह अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है। जन-संवाद से समाधान अभियान के तहत अब शिकायतों को सिर्फ कागजों में नहीं दबाया जा रहा, बल्कि तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। फरियादियों को अनावश्यक परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे खास बात यह रही कि 22 अप्रैल को कार्यभार संभालने के बाद से अब तक कार्यालय दिवसों में कुल 1406 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1244 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

इनमें राजस्व विभाग की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं, जिनमें अवैध कब्जा, पैमाइश, अतिक्रमण और चकरोड विवाद प्रमुख रहे। डीएम ने कहा कि जन-संवाद से समाधान केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच भरोसे का पुल है। इस अभियान से न केवल समस्याओं के समाधान की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत होगी। डीएम की यह पहल अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है और लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव मान रहे हैं।

राइस कुकर में सही तरीके से खाना पकाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल सुझाव

उपकरण

राइस कुकर एक उपयोगी उपकरण है, जो चावल को सही तरीके से और जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि राइस कुकर केवल चावल पकाने के लिए होता है तो आपको बता दें कि आप इससे पुलाव, खिचड़ी, दलिया, दाल और यहां तक कि केक भी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप राइस कुकर में हर बार सही तरीके से खाना पका सकते हैं।

पानी का सही अनुपात रखें

राइस कुकर में खाना पकाने के लिए सही मात्रा में पानी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप चावल बना रहे हैं तो आमतौर पर एक कप चावल के लिए 2 कप पानी का उपयोग करना चाहिए। पुलाव या खिचड़ी के लिए भी इसी अनुपात का पालन करें। दाल और दलिया के लिए 1:3 का अनुपात सही रहता है। इससे आपका खाना न तो कच्चा रहेगा और न ही ज्यादा गीला होगा।

समय का ध्यान रखें

राइस कुकर में खाना पकाने का समय भी बहुत अहम होता है। आमतौर पर चावल पकाने में 20-25 मिनट लगते हैं, जबकि पुलाव और खिचड़ी को पकाने में 30-40 मिनट का समय लगता है। दाल और दलिया को पकाने में भी लगभग इसी समय की जरूरत होती है। अगर आप केक बना रहे हैं तो इसे 50-60 मिनट तक पकाएं। सही समय पर खाना पकाने से आपका खाना न तो अधपका होगा और न ही ज्यादा पका हुआ।

को सही तरीके से भरें

राइस कुकर के बर्तन को सही तरीके से भरना भी जरूरी है। इसे ज्यादा भरने से खाना उबलकर बाहर आ सकता है, इसलिए इसे आधा या 3/4 तक ही भरें। इससे खाना अच्छे से पकेगा और बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा राइस कुकर के अंदर रखी प्लेट को हमेशा हल्का-सा घुमाकर रखें, ताकि भाप निकल सके और खाना अच्छे से पक सके। इससे आपका खाना हर बार सही तरीके से बनेगा।

सब्जियों को पहले से तैयार करें

अगर आप पुलाव या खिचड़ी बना रहे हैं तो सब्जियों को पहले से काटकर तैयार कर लें। इससे खाना पकाने का समय कम होगा और आपका खाना लजीज बनेगा। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर राइस कुकर में डालें और फिर ऊपर से चावल डालें। इसके बाद जरूरी मसाले और पानी मिलाएं। इससे आपका पुलाव और खिचड़ी एकसार बनेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। इस तरह आप अपने राइस कुकर का सही उपयोग कर सकते हैं।

साफ-सफाई पर ध्यान दें

राइस कुकर की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इसमें कीटाणु न पनप सकें। इस्तेमाल करने के बाद इसे धोकर सुखाएं और समय-समय पर इसकी सफाई करें। इन सरल सुझावों की मदद से आप अपने राइस कुकर में हर बार बेहतरीन खाना बना सकते हैं। इनका पालन करके न केवल आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आपका राइस कुकर लंबे समय तक सही तरीके से काम कर रहा है।

जंक फूड खाने के बाद शरीर थका हुआ क्यों महसूस होता है?

जंक फूड का सेवन आजकल काफी आम हो गया है। इसका स्वाद भले ही लाजवाब हो, लेकिन यह सेहत पर बुरा असर डालता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जंक फूड खाने के बाद उनका शरीर थका हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं कि जंक फूड खाने के बाद शरीर थका हुआ क्यों महसूस होता है और इससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

जंक फूड में जरूरी पोषक तत्वों की कमी

जंक फूड में अक्सर विटामिन, खनिज और फाइबर की कमी होती है। इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर को सही तरीके से काम करने में दिक्कत होती है। इससे ऊर्जा का स्तर गिरता है और आपको थकान महसूस होती है। जंक फूड खाने से शरीर को वो जरूरी पोषण नहीं मिलता, जो उसे चाहिए होता है, जिससे आप सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है।

ज्यादा शक्कर और चर्बी का प्रभाव

जंक फूड में ज्यादा मात्रा में शक्कर और चर्बी होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन इसके बाद तेजी से ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। इससे आपको जल्द ही थकान महसूस होती है और मूड भी खराब हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा शक्कर और चर्बी का सेवन लंबे समय तक सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे मोटापा, मधुमेह और दिल की बीमारियां जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

पाचन पर पड़ता है बुरा असर

जंक फूड पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है, जिससे पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे कब्ज, गैस, और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जंक फूड का सेवन पाचन की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर को सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए यह जरूरी है कि हम संतुलित आहार लें, जिसमें फाइबर, विटामिन्स और खनिज भरपूर मात्रा में हों ताकि पाचन सही तरीके से काम कर सके।

नींद का खराब होना

जंक फूड में अधिक मात्रा में कैफीन या अन्य उत्तेजक तत्व हो सकते हैं, जो नींद को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जंक फूड का सेवन रात में करने से पाचन क्रिया बाधित होती है, जिससे नींद भी खराब होती है। इससे आप अगली सुबह थका हुआ महसूस करते हैं और आपकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए बेहतर होगा कि रात के समय हल्का और पौष्टिक भोजन ही किया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है प्रभाव

जंक फूड खाने से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जंक फूड खाने से ध्यान केंद्रित करने में भी दिक्कत होती है, जिससे काम में बाधा आती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंक फूड खाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक थकान भी होती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम संतुलित आहार लें।

इटली से कम नहीं है भारत की ये जगह, इस गर्मी घूमने का बना लें प्लान

भारत में कई ऐसी जगह हैं, जो विदेश जैसी फील देती हैं। फिर चाहे भारत का मिनी थाईलैंड हो या फिर मिनी न्यूजीलैंड।।।आज इस आर्टिकल में हम आपको भारत का इटली कहे जाने वाली जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत है।

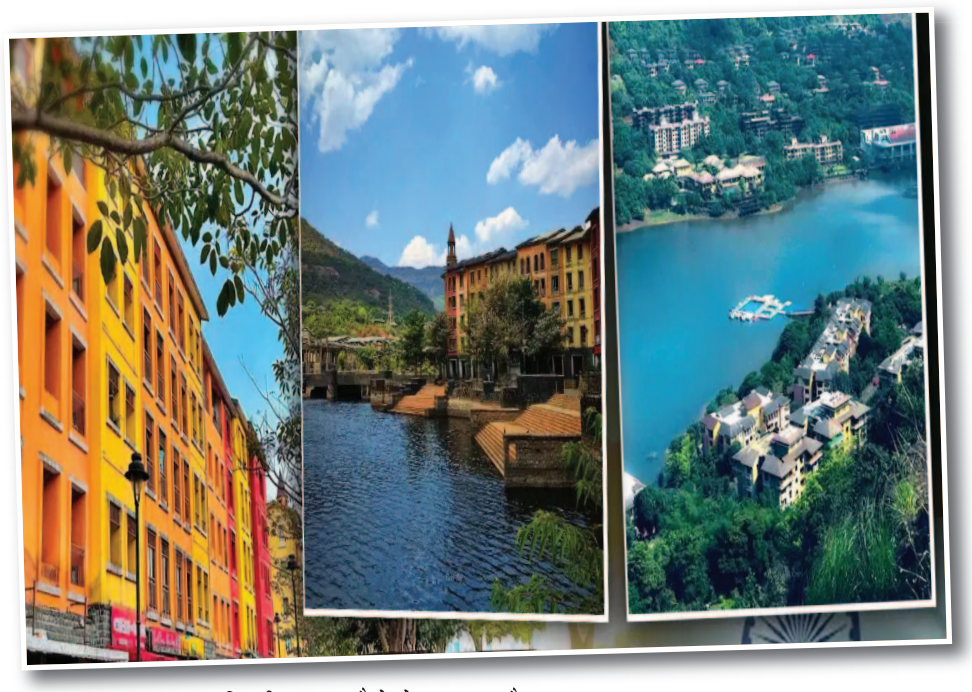

भारत कितनी खूबसूरत है ये तो हम सब जानते ही हैं। यहां कई ऐसी जगह हैं, जिसकी खूबसूरती विदेशों को भी फेल कर देती है। भारत में आपको न सिर्फ मिनी थाईलैंड और न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। बल्कि यहां एक ऐसी जगह भी है, जो पूरा इटली वाला फील देती है। जी हां, महाराष्ट्र की खूबसूरत वादियों में बसा लवासा किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। रंग-बिरंगी इमारतें, शांत झील, घुमावदार सड़कें और चारों तरफ फैली हरियाली इसे ऐसा नजारा देती हैं, जिसे देखकर इटली के छोटे-छोटे टाउन याद आ जाते हैं।

गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप भीड़भाड़ और शोर से दूर किसी सुकून भरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो लवासा आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। यहां की ठंडी हवाएं, खूबसूरत कैफे, झील किनारे का नज़ारा और एडवेंचर एक्टिविटीज हर उम्र के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। साथ ही यहां कैसे पहुंच सकते हैं।

इटली जैसा फील देता है लवासा

महाराष्ट्र की लवासा उन जगहों में से एक है जहां पहुंचते ही आपको यूरोप जैसा फील मिलेगा। यहां आपको इटली जैसी रंग बिरंगी इमारतें, झील के किनारे बने कैफे, साफ-सुथरी सड़कें और शांत वातावरण इसे किसी इटैलियन टाउन जैसा लुक देते हैं। पुणे के पास स्थित यह हिल सिटी गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन माना जाता है। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, इसलिए कपल्स, फैमिली और दोस्तों के ग्रुप के बीच यह जगह काफी पॉपुलर है।

लवासा की क्या है खासियत

लवासा की सबसे खास बात है यहां बना प्लांन्ड हिल सिटी थीम। जो इटली के पोर्टोफिनो शहर से इंस्पायर है। यहां की झील, वॉटरफ्रंट प्रोमेनेड, यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर और हरियाली लोगों को बेहद आकर्षित करती है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो भी यहां कई एक्विटी कर सकते हैं। वहीं सुकून पसंद लोगों के लिए भी यहां खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं।

लवासा में क्या-क्या करें एक्सप्लोर

लवासा में घूमने की बात करें तो यहां कई जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां की लेकसाइड प्रोमेनेड सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जहां शाम के वक्त घूमने का अलग ही मजा होता है। इसके अलावा टेमघर डैम, दासवे व्यू पॉइंट और आसपास की हरी-भरी घाटियां भी टूरिस्ट्स को खूब आकर्षित करती हैं। एडवेंचर लवर्स यहां जेट स्की, कायकिंग और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। वहीं, कैफे और रेस्टोरेंट्स में बैठकर झील के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना भी यहां का खास एक्सपीरियंस माना जाता है।

दिल्ली और मुंबई से कैसे पहुंचे लवासा

लवासा पहुंचना भी काफी आसान है। अगर आप मुंबई में रहते हैं और लवासा जाना चाहते हैं तो इसकी दूरी 190 किलोमीटर है। बाए रोड जाने पर 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। वहीं दिल्ली से लवासा जाने के लिए फ्लाइट एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले आपको पुणे पहुंचना है और वहां से टैक्सी लेकर लवासा जा सकते हैं। रोड ट्रिप पसंद करने वालों के लिए मुंबई-पुणे-लवासा का सफर बेहद खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि रास्ते में पहाड़, झरने और हरियाली सफर को यादगार बना देते हैं।

जींस की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, रंग हो सकता है फीका

जींस एक ऐसा कपड़ा है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाता है। हालांकि, अगर जींस की देखभाल सही तरीके से न की जाए तो उसका रंग फीका पड़ सकता है। अक्सर हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे हमारी पसंदीदा जींस का लुक बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे जींस का रंग फीका पड़ सकता है।

गर्म पानी में न धोएं

गर्म पानी में जींस धोने से उसके रंग पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्म पानी से कपड़े की बुनावट ढीली पड़ सकती है, जिससे जींस का रंग भी फीका पड़ सकता है। हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से धोने से रंग बरकरार रहता है और कपड़े की मजबूती भी बनी रहती है। यह तरीका न केवल रंग को सुरक्षित रखता है, बल्कि कपड़े को भी लंबे समय तक नया बनाए रखता है।

ज्यादा साबुन का इस्तेमाल न करें

जींस धोते समय ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करने से भी उसका रंग फीका पड़ सकता है। ज्यादा साबुन से रंग निकल सकता है और कपड़े की मजबूती भी खराब हो सकती है। इसलिए, हमेशा थोड़ी मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें। इससे न केवल आपकी जींस का रंग बरकरार रहेगा, बल्कि उसकी मजबूती भी बनी रहेगी। सही मात्रा में साबुन का उपयोग करने से आपकी पसंदीदा जींस लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और आरामदायक भी बनी रहेगी।

जींस को उल्टा करके धोएं

जींस को धोते समय उसे उल्टा कर लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे बाहरी सतह पर लगे धब्बे आसानी से निकल जाते हैं और रंग भी फीका नहीं पड़ता। इसके अलावा उल्टी तरफ से धोने से कपड़े की बनावट पर कम असर पड़ता है, जिससे उसकी मजबूती बनी रहती है। यह तरीका न केवल जींस की सफाई में मदद करता है, बल्कि उसके रंग को भी सुरक्षित रखता है।

अधिक समय तक मशीन में न रखें

अधिक समय तक मशीन में रखने से जींस की बनावट कमजोर हो सकती है और उसका रंग भी फीका पड़ सकता है। इसलिए, जब आपकी जींस धो ली जाए तो उसे तुरंत बाहर निकालें और हवा में सुखाएं। इससे न केवल उसकी मजबूती बनी रहती है, बल्कि उसका रंग भी बरकरार रहता है। इस तरह आपकी पसंदीदा जींस लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और आरामदायक भी बनी ही रहेगी।

ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें

ड्रायर का इस्तेमाल करने से जींस का रंग भी फीका पड़ सकता है और उसकी फिटिंग भी बिगड़ सकती है। ड्रायर की गर्म हवा से कपड़े की बनावट कमजोर हो सकती है, जिससे उसकी मजबूती प्रभावित होती है। इसलिए, हमेशा प्राकृतिक तरीके, जैसे हवा में सुखाने का सहारा लें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पसंदीदा जींस को लंबे समय तक नई जैसी दिखा सकते हैं और उसकी मजबूती भी बनी रहती है।

अब चुटकियों में यूपीआई से निकलेगा पीएफ का पैसा, पूरी हुई टेस्टिंग

नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जल्द ही कर्मचारी अपने ईपीएफओ खाते से यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस नई और आसान व्यवस्था से करीब सात करोड़ कर्मचारियों को तुरंत फंड मिल सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा निकालना हमेशा से एक लंबी प्रक्रिया मानी जाती रही है। लेकिन, अब नौकरीपेशा वर्ग को जल्द ही इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक बेहद अहम अपडेट साझा किया है। जल्द ही आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करके अपना पीएफ फंड सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। इस बदलाव की तकनीकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

पुरानी व्यवस्था में लगता है लंबा वक्त

वर्तमान समय में पीएफ निकासी की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। किसी भी कर्मचारी को फंड निकालने के लिए पहले ऑनलाइन क्लेम फाइल करना होता है। इसके बाद विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है, जिसके बाद ही फंड बैंक खाते में क्रेडिट होता है। इस पूरी कागजी कार्यवाही में कई दिन लग जाते हैं। हालांकि, ईपीएफओ ने हाल ही में अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत निकासी सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इस ऑटो-सेटलमेंट से कुछ मामलों में महज तीन दिन में भुगतान हो जाता है, फिर भी आम कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया कई बार पेचीदा साबित होती है।

बस तीन आसान चरणों में ट्रांसफर होगा फंड

नई सुविधा के लाइव होते ही पीएफ का पैसा निकालना किसी को यूपीआई से पेमेंट करने जितना ही आसान हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन आसान चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले, आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा, जहां डैशबोर्ड पर निकासी योग्य राशि दिखाई देगी। दूसरे चरण में, आपको उस बैंक खाते का चयन करना होगा जो आपके यूपीआई से लिंक है। इसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन दर्ज करके ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करना होगा। तीसरे तथा अंतिम चरण में, यह प्रक्रिया पूरी होते ही फंड तुरंत आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। इस पैसे का उपयोग आप किसी भी यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एटीएम से नकदी निकालने के लिए कर सकेंगे।

सात करोड़ सदस्यों को मिलेगी फौरी राहत

इस नई तकनीक का सीधा फायदा देश के सात करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को मिलने वाला है। जीवन में कई बार अचानक आर्थिक जरूरतें आ खड़ी होती हैं। चाहे वह किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो, बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च हो, घर का निर्माण हो या फिर शादी-ब्याह का मामला, ऐसे समय में तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है। यूपीआई निकासी सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ तरलता भी प्रदान करेगा।

पोस्ट ऑफिस की सुपरहिट स्कीम... 2 लाख लगाएं, 90 हजार रुपये का सीधा फायदा पाएं!

शेयर बाजार के रिस्क से दूर, अगर आप अपने खून-पसीने की कमाई पर पक्की गारंटी चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की 'टाइम डिपॉजिट स्कीम' (TD) आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको कई बड़े सरकारी बैंकों की एफडी (FD) से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। सबसे बड़ी बात, आपका एक-एक पैसा सरकार की गारंटी के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

इस स्कीम में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 से 5 साल तक के लिए पैसा लॉक कर सकते हैं। फिलहाल सरकार 1 साल की जमा पर 6.9%, 2 और 3 साल के लिए 7% का ब्याज दे रही है। लेकिन सबसे तगड़ा मुनाफा 5 साल के निवेश में है, जहां आपको 7.5% का छप्परफाड़ सालाना ब्याज मिलता है।

अब जरा मुनाफे का सीधा गणित समझिए। अगर आप इस स्कीम में 5 साल के लिए 2 लाख रुपये एकमुश्त जमा कर देते हैं, तो 7.5% ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद आपको कुल 2,89,990 रुपये मिलेंगे। यानी बिना कुछ किए, बैठे-बिठाए करीब 90 हजार रुपये (₹89,990) की पक्की कमाई सिर्फ और सिर्फ ब्याज से हो जाएगी!

इस सरकारी स्कीम की सबसे अच्छी बात ये है कि आप मात्र 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और निवेश की कोई ऊपरी सीमा (Maximum limit) नहीं है। जितना पैसा लगाएंगे, ब्याज उतना ही ज्यादा मिलेगा। आप चाहें तो अकेले (Single) या किसी के साथ मिलकर (Joint) अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चों के नाम पर भी खाता खुलवाया जा सकता है।

अगर आप 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में शानदार छूट भी मिलती है। बस एक शर्त ध्यान रखें, खाता खुलने के पहले 6 महीने तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर किसी मजबूरी में समय से पहले पैसा निकालना पड़ा, तो ब्याज में 1% तक की कटौती (जुर्माना) हो सकती है।

सुरक्षित निवेश और तगड़े रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम बेहतरीन है। इसमें 5 साल के निवेश पर 7.5% का दमदार ब्याज मिल रहा है। यानी अगर आप 2 लाख रुपये लगाते हैं, तो 5 साल बाद लगभग 90 हजार रुपये सिर्फ ब्याज से कमाएंगे। सरकारी गारंटी वाली इस योजना में टैक्स छूट का भी बड़ा फायदा मिलता है।

करीब 85 लाख से अधिक डेवलपर्स गूगल एआई मॉडल का कर रहे इस्तेमाल, 190 अरब डॉलर का निवेश करेगी कंपनी : सुंदर पिचाई

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि 85 लाख से अधिक डेवलपर्स हर महीने कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल का इस्तेमाल कर ऐप बना रहे हैं। पिचाई ने ब्लॉग में कहा कि गूगल इस साल एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में 190 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है, जो कि एआई डेटा सेंटर्स, कस्टम सिलिकॉन और मॉडल ट्रेनिंग पर केंद्रित होगा।

पिचाई ने आगे कहा कि कंपनी अपने एआई इकोसिस्टम में तेज ग्रोथ देख रही है, और डेवलपर्स, उद्यमों और उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग बढ़ रही है। गूगल के अनुसार, इसके मॉडल एपीआई अब प्रति मिनट लगभग 19 अरब टोकन प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 375 से अधिक गूगल क्लाउड ग्राहकों ने प्रत्येक ने एक ट्रिलियन से अधिक टोकन प्रोसेस किए।

गूगल के एआई उत्पादों के बढ़ते उपयोग का जिक्र करते हुए पिचाई ने कहा कि कंपनी के जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 900 मिलियन से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। एआई-संचालित सर्च को भी जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है, एआई ओवरव्यू के मासिक यूजर्स की संख्या 2.5 अरब से अधिक हो गई है और एआई मोड के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या एक अरब से अधिक हो गई है।

कंपनी ने कई नए एआई टूल और अपग्रेड भी पेश किए, जिनमें जेमिनी 3.5 फ्लैश शामिल है, जो कोडिंग और रिल्य वर्ल्ड वर्कफ्लो पर केंद्रित एक तेज एआई मॉडल है और जेमिनी स्पार्क, एक नया व्यक्तिगत एआई एजेंट है जिसे यूजर्स की ओर से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है।

गूगल ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अपडेट पेश किए हैं, जिनमें नवीनतम पीढ़ी के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (टीपीयू) शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर एआई प्रशिक्षण और अनुमान प्रक्रिया को तेज करने में सहायक हैं।

ईरान के बाद अब क्यूबा की बारी?: ट्रंप ने बताया नाकाम देश, कहा- यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों नेताओं ने क्यूबा को एक 'नाकाम देश' करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्यूबा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। फ्लोरिडा और व्हाइट हाउस में अलग-अलग बयानों में दोनों अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे क्यूबा के प्रति अब और भी सख्त रवैया अपनाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है।

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यूबा के लोगों और वहां से आकर अमेरिका में बसे लोगों की मदद करना चाहता है। ट्रंप ने क्यूबा की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक नाकाम देश है और यह बात हर कोई जानता है। उन्होंने बताया कि वहां बिजली नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और खाने-पीने की चीजों की भी भारी कमी है।

ट्रंप ने कहा कि वे इंसानियत के नाते क्यूबा की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबा मूल के अमेरिकी अपने देश में निवेश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 50-60 वर्षों से कई राष्ट्रपति इस बारे में सोचते रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि इस समस्या को वे ही सुलझा पाएंगे।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्या कहा?

दूसरी तरफ, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियामी एयरपोर्ट पर और भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्यूबा लगातार अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। रुबियो ने याद दिलाया कि क्यूबा अमेरिकी तट से सिर्फ 90 मील दूर है। वहां एक ऐसी सरकार है जिसे अमेरिका के दुश्मनों के दोस्त चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं। वहां इन दोनों देशों के हथियार सिस्टम भी पहुंच चुके हैं। रुबियो ने क्यूबा पर लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।

व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी इन चिंताओं को दोहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि क्यूबा अमेरिका के दुश्मनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। मिलर ने कहा कि अमेरिका का कोई भी दुश्मन क्यूबा से हमला करने वाले ड्रोन भेज सकता है। ये ड्रोन वहां से बहुत आसानी से अमेरिकी सीमा तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अपने इतने करीब दुश्मनों या आतंकवादियों का ठिकाना बर्दाश्त नहीं करेगा। रुबियो ने अंत में कहा कि अमेरिका मानवीय सहायता देने को तैयार है, लेकिन यह मदद क्यूबा की सेना के बजाय केवल स्वतंत्र समूहों के माध्यम से ही दी जाएगी।

नए आदेश से बढ़ी मैक्सिको की चिंता, राष्ट्रपति शीनबॉम ने उठाया ये कदम

मैक्सिको सिटी, एजेंसी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा है कि उनकी सरकार अमेरिका के नए आदेश का असर का विश्लेषण कर रही है। यह आदेश उन प्रवासियों पर लागू हो सकता है जो बिना कानूनी दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। इसके तहत ऐसे लोगों के लिए अमेरिकी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो सकती है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति शीनबॉम से उनकी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या इस फैसले का असर अमेरिका से मैक्सिको भेजे जाने वाले पैसों पर पड़ेगा। ये वही पैसे हैं, जिन्हें वहां काम कर रहे मैक्सिकन नागरिक अपने परिवारों को भेजते हैं। उन्होंने बताया कि मैक्सिको का वित्त मंत्रालय और अमेरिका में नए मैक्सिकन राजदूत रॉबर्टो लाजेरी मिलकर इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल उनकी शुरुआती राय है कि इससे कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा।

अमेरिका ने उठाया क्या कदम?

अमेरिका का यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीमा-पार होने वाले पैसों के लेन-देन और बैंक खाते खोलने या अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली पहचान-पत्रों की निगरानी को और सख्त बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस नए कदम से अब बैंक और वित्तीय रिकॉर्ड भी इमिग्रेशन जांच के दायरे में आ सकते हैं। इससे कई प्रवासियों की गतिविधियों पर ज्यादा नजर रखी जा सकती है। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप ने 19 मई को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें बैंकों और वित्तीय नियामक संस्थाओं को कहा गया है कि वे ग्राहकों की नागरिकता और इमिग्रेशन स्थिति से जुड़े संदिग्ध संकेतों पर नजर रखें। यह कदम अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

प्रवासियों पर क्या बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'इनमें से कई कर्जदारों को देश से निकाले जाने का डर है। या फिर उनके नियोक्ताओं (मालिकों) द्वारा इमिग्रेशन कानूनों का पालन करने के कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कानूनी तौर पर काम करने की अनुमति न रखने वाले विदेशियों को कर्ज देना बैंकिंग व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जिन लोगों पर कमाई बंद होने का बड़ा जोखिम हो, उन्हें ऋण देने से 'कर्ज चुकाने की क्षमता' का संकट पैदा होता है। यह स्थिति हमारी राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती है।'

चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी : अमेरिका में नया बिल पेश, ड्रैगन के सैन्य नेटवर्क पर लगाना चाहता है प्रतिबंध

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दो वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य-औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नया विधेयक पेश किया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली चीनी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में अब और देरी नहीं की जा सकती।

रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस स्टेफानिक ने 'सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट' नाम का विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ एक साल के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जिन्हें अमेरिकी सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है। इसके तहत एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी, जिसके भीतर संदिग्ध चीनी संस्थाओं को ट्रेजरी विभाग की 'नॉन-एसडीएन चीनी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कंपनियों की सूची' में शामिल करना अनिवार्य होगा।

मौजूदा कानून के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति हर दो साल में ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें उन चीनी व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जाती है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माना जाता है। हालांकि, अभी ट्रेजरी विभाग के लिए इन संस्थाओं पर कार्रवाई या सूची अपडेट करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। नया विधेयक इसी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करता है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति की रिपोर्ट पेश होने के एक साल के भीतर ट्रेजरी सचिव को संबंधित विदेशी नागरिकों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल करना होगा और संशोधित सूची को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित करना होगा।

रिक स्कॉट ने क्या बताया?

सीनेटर रिक स्कॉट ने कहा कि जैसे ही किसी संस्था की पहचान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में होती है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य हितों के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को अमेरिका में कारोबार करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कम्युनिस्ट चीन हमारा दुश्मन है और अब उसी के अनुरूप सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। वहीं, एलिस स्टेफानिक ने कहा कि यह विधेयक चीन के सैन्य विस्तार से जुड़ी कंपनियों पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

रिपोर्ट का दावा– ईरान कर सकता है अचानक हमला, युद्धविराम पर बातचीत के बीच खौफ में नेतन्याहू

तेल अवीव, एजेंसी। इस्रायल को अंदेशा है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। यह डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। 'जेरूसलम पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की जानकारी दी है।

इस खतरे को देखते हुए इस्रायल के रक्षा मंत्री इस्रायल काट्ज और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के शुरुआती चरणों से की है।

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कुछ मतभेदों की खबरें भी आई हैं। इसके बावजूद, दोनों देशों की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस्रायली वायुसेना और आईडीएफ (IDF) के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हमले की स्थिति में मिलकर जवाब दिया जा सके।

पिछले एक महीने में अमेरिका से इस्रायल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है। दोनों देशों ने मिलकर मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और सॉफ्टवेयर को और भी बेहतर बनाया है। 'वल्ला' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खतरों की पहचान करने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है।

राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने साफ किया कि वे ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेकर उसे नष्ट कर देंगे। माना जाता है कि ईरान के पास करीब 900 पाउंड अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो हथियार बनाने के लिए काफी है। इस्रायल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। इस्रायल का मानना है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है।

दुश्मन पर चील की तरह मंडराएगा वायु अस्त्र-1, भारत का नया कामकाजी ड्रोन बना गेमचेंजर

नई दिल्ली, एजेंसी। डिफेंस सेक्टर भारतीय कंपनी 'नाइब ग्रुप' ने अपने नए खतरनाक हथियार वायु अस्त्र-1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। यह एक ऐसा घातक 'कामिकाजे' या सुसाइड ड्रोन है, जो आसमान में चील की तरह मंडराता रहता है और टारगेट मिलते ही खुद को उससे टकराकर ब्लास्ट कर देता है। हाल ही में भारतीय सेना के सामने इसका 'नो-कॉस्ट, नो-कमिटमेंट' (NCNC) के तहत राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ (मलारी) में सफल लाइव प्रदर्शन हुआ।

पोखरण रेंज में 'वायु अस्त्र-1 एंटी-पर्सनल' ड्रोन ने 10 किलो वजनी वॉरहेड (विस्फोटक) के साथ उड़ान भरी और पहली ही बार में 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया।

इस सिस्टम ने एक ही बार में 100km की दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद दिया। इस दौरान इसकी 'सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी' (CEP) 1 मीटर से भी कम रहा, जिसका मतलब है कि यह अपने तय टारगेट से 1 मीटर भी नहीं भटका।

इसमें हमला रोकने की खूबी है। इसमें एक खास तकनीक है, जिसके जरिए अगर ड्रोन हमले के लिए आगे बढ़ चुका है, तो आखिरी समय में भी उस हमले को रोका जा सकता है और दोबारा नए सिरे से हमला (Re-attack) किया जा सकता है। यह ड्रोन इजराइली तकनीक पर आधारित है।

रात के अंधेरे में लक्ष्यों को भेद दिया

राजस्थान के पोखरण में ही इस टीम ने रात के अंधेरे में 'एंटी-आर्मर'(एंटी-टैंक) नाइट स्ट्राइक का भी टेस्ट किया। इंफ्रारेड (IR) कैमरे की मदद से इस ड्रोन ने रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंकों को खोज निकाला और महज 2 मीटर की सटीकता के साथ उन पर सटीक हमला किया। इस टेस्ट के दौरान ड्रोन के कंट्रोल को 70 किलोमीटर दूर बैठे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS) से फॉरवर्ड कंट्रोल सेगमेंट (आगे तैनात टीम) को सुरक्षित ट्रांसफर करने का भी सफल प्रदर्शन किया गया।

उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भरी उड़ान

रेगिस्तान के बाद 'वायु अस्त्र-1' की असली परीक्षा उत्तराखंड के जोशीमठ (मलारी) की पहाड़ियों में हुई। यह एक हाई-अल्टीट्यूड टेस्ट था। इस ड्रोन ने 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई और बेहद कम तापमान वाले पहाड़ी इलाके में शानदार प्रदर्शन किया। ड्रोन ने हवा में 90 मिनट से ज्यादा समय तक मंडराने (Loitering) और उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन के पूरा होने के बाद इस ड्रोन को सुरक्षित रिकवर (वापस लैंड) करा लिया गया, यानी इसे अगली उड़ान के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र में क्यों अहम है यह कामयाबी?

आधुनिक युद्धों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए यह ड्रोन गेमचेंजर साबित होने वाला है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर ऊंचे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में यह ड्रोन दुश्मनों के बंकरों, गाड़ियों और सैनिकों पर छिपकर हमला करने में माहिर है। रात के अंधेरे में भी काम करने की इसकी क्षमता भारत की सैन्य ताकत को बॉर्डर पर कई गुना बढ़ा देती है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा होगी और पुख्ता, तेज हुआ बाड़बंदी का काम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा के उन संवेदनशील और खुले हिस्सों (Unfenced patches) में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बाड़ लगाने (Fencing) का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, जो सालों से सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती बने हुए थे।

हाल ही में राज्य में राजनीतिक बदलाव और नई भाजपा सरकार के गठन के बाद, पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े भूमि अधिग्रहण के मामलों में तेजी आई है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए बीएसएफ को बाड़बंदी के लिए जमीन सौंपने की प्रक्रिया को गति दे दी है।

बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर 24 परगना और दूसरे सीमावर्ती जिलों के 'चक्रबंदा' जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन के साथ मिलकर भूमि का संयुक्त जायजा लिया।

बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया, "जमीन सौंपने की प्रक्रिया अब बेहद सुचारू रूप से चल रही है। जल्द ही करीब 27 किलोमीटर लंबे एक बड़े और बेहद संवेदनशील हिस्से समेत कई अन्य पैच की जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। प्रशासन और स्थानीय लोगों से मिल रहा सहयोग इस काम को तेजी से पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है।"

क्यों अहम है यह बाड़बंदी?

भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 569 किलोमीटर हिस्से पर अब तक बाड़बंदी नहीं हो पाई है। इस खुले क्षेत्र के कारण घुसपैठ, मवेशी तस्करी, नकली नोट और ड्रग्स की तस्करी जैसी घटनाएं होती रहती हैं और यही खुला बॉर्डर का रास्ता BSF और सुरक्षा बलों के लिए मुख्य चुनौती बना हुआ है। इस 569 किलोमीटर के खुले हिस्से में नदी क्षेत्र (Riverine borders), घने रिहायशी इलाके और खेती योग्य जमीनें शामिल हैं, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व आसानी से सीमा पार कर लेते थे।

अपराधों पर लगेगी लगाम, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत

बीएसएफ के मुताबिक, इस बाड़बंदी के पूरा होने से सीमा पर न केवल घुसपैठ और मानव तस्करी पर पूरी तरह रोक लगेगी, बल्कि मवेशियों और प्रतिबंधित सामानों की तस्करी पर भी प्रभावी लगाम कसी जा सकेगी। अत्याधुनिक बाड़ के साथ-साथ इस पूरे कॉरिडोर में फ्लड लाइट्स, एंटी-कट सेंसर और नाइट-विज़न कैमरों से लैस स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है।

तकनीकी निगरानी भी होगी मजबूत

सूत्रों के अनुसार, जिन इलाकों में नदी या दलदली भूमि होने के कारण भौतिक बाड़ लगाना मुमकिन नहीं है, वहां 'तकनीकी बाड़' का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पानी के भीतर काम करने वाले सेंसर और थर्मल इमेजर शामिल हैं, ताकि निगरानी प्रणाली में एक इंच का भी 'ब्लाइंड स्पॉट' न रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल के चलते माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के भीतर इस मिशन के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे देश की पूर्वी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।

साइप्रस में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनेगी 'इश्का', निर्देशक का करण जौहर से है खास नाता

अंजलि भूषण मागो ने गुरुवार को अपनी फीचर फिल्म 'इश्का' की घोषणा कर दी है। एक इवेंट में उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह पहली भारतीय फीचर फिल्म है जिसकी शूटिंग साइप्रस में होगी।

करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अंजली भूषण मागो जल्द ही अपनी पहली फिल्म पर काम शुरू करेंगी। 'इश्का' नाम से बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। खास बात यह है कि ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो साइप्रस में शूट होगी। इस बारे में फिल्म के मेकर्स और साइप्रस के अधिकारियों ने शेयर की है।

साइप्रस के राष्ट्रपति ने जताई खुशी

फिल्म 'इश्का' की शूटिंग पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'साइप्रस में पहली बॉलीवुड फिल्म शूट होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आगे और भी कई सहयोगों की शुरुआत होगी। यह साइप्रस के लिए भरोसे का एक बड़ा संकेत है और मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगा। हम इस शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं। पिछले साल जून में साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। यह हमारे संबंधों में एक नए युग की शुरुआत थी। हमने एक नया अध्याय शुरू किया है और हम फिल्म निर्माण सहित सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।'

इवेंट में मौजूद रहे कई सितारे

फिल्म 'इश्का' के अनाउंसमेंट इवेंट पर कई सितारों ने शिरतक की। इस मौके पर जावेद जाफरी, रवि किशन, श्रेया धनवंतरी, एलनाज नौरोजी, गौरव चोपड़ा, अदिती पोहनकर, प्रीति पाणिग्रही उपस्थित रहे। 'इश्का' एक रोमांटिक कॉमेडी फीचर फिल्म है जिसकी कहानी भी अंजलि भूषण मागो ने लिखी है।

इस फिल्म के जरिए 'बेबी डॉल' और 'चिट्टियां कलाइयां' जैसे सुपरहिट गाने देने वाली म्यूजिक कंपोजर जोड़ी मीत ब्रोस भी प्रोडक्शन फील्ड में अपना डेब्यू करेंगी। वो इस फिल्म के कई को-प्रोड्यूसर्स में से एक होंगे।

कॉर्सेट गाउन में दिखीं जैकलीन फर्नांडीज, कान फेस्टिवल में चलाया हुस्न का जादू

जैकलीन फर्नांडिज का कान फिल्म फेस्टिवल से एक और लुक वायरल हो रहा है। इस लुक में उनका बोल्ड अंदाज फैंस को देखने को मिल रहा है। यहां देखिए, जैकलीन फर्नांडिज की अनदेखी तस्वीरें।

पिछले दिनों जैकलीन फर्नांडिज भी कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंची थीं। पहले उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस ड्रेस से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच तहलका मचा दिया। अब अपना एक और लुक कान फेस्टिवल से इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस लुक में भी वह कहर ढाह रही हैं। कैसा है, जैकलीन का लुक, यहां जानिए।

जैकलीन ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर कान फिल्म फेस्टिवल से कई तस्वीरें साझा की हैं। इसमें वह बॉडी फिटेड आइवरी कलर का कॉर्सेट गाउन पहने नजर आ रही हैं। इस गाउन के साथ जैकलीन ने काले रंग के गलव्स पहने हैं। जिससे उनका लुक अलग और खास नजर आ रहा है।

गाउन में 3डी स्टाइल का फ्लावर पैटर्न भी फैंस का ध्यान जैकलीन की तरफ खींच रहा है। यह गाउन लुक विंटेज फैशन से इंस्पायर है। जैकलीन ने अपने गाउन लुक के साथ हाईबन हेयरस्टाइल बनाया है। अपनी ड्रेस के साथ डायमंड नेकलेस और ईयररिंग जैकलीन ने पहने हैं और अपने लुक को कंप्लीट किया है।

इस ड्रेस में वह अलग-अलग तरह के दिलकश पोज भी दे रही हैं। कान फेस्टिवल में एक संस्था ग्लोबल गिफ्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में जैकलीन शामिल हुईं। इसी मौके पर उन्होंने यह गाउन लुक पहना था। इस इवेंट में शामिल होकर एक्ट्रेस काफी खुश नजर आईं। जैकलीन के करियर फ्रंट की बात करें तो जल्द ही वह फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भी अक्षय कुमार के साथ एक्टिंग करेंगी। इस फिल्म में दिशा पाटनी भी नजर आएंगी।

'बौखला गए लोग...', आधी रात अमिताभ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, मतलब खोजने जुटे यूजर्स, बोले – 'आपके विचार केवल आप'

दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अक्सर अपने पोस्ट के जरिए फैंस के बीच सस्पेंस बना कर रखते हैं। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने ऐसा पोस्ट किया जिसे यूजर्स समझ नहीं पा रहे। इस पोस्ट पर उनके फैंस के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए हैं।

83 वर्षीय अभिनेता ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'बौखला गए लोग, विचार व्यक्त किए, कोई समझे या न समझे, लिए के दिए बन गए जरूर'। अब इस पोस्ट पर यूजर्स कमेंट करते हुए इसका मतलब खोज रहे हैं। कुछ यूजर्स ने जहां इस पोस्ट का साहित्यिक मतलब निकालने की कोशिश की तो वहीं अन्य यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया।

यूजर्स ने किए पोस्ट पर कमेंट

अमिताभ की इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट्स किए। कुछ यूजर्स ने जहां पोस्ट का राजनैतिक मतलब निकालने की कोशिश की। वहीं कुछ ने इस पर बिग बी का ही मजाक बनाया। एक यूजर ने लिखा, 'आपके विचार ऐसे हैं जिन्हें केवल आपका अपना दिमाग ही समझ सकता है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,' विचार में अवश्य सच्चाई होगी, बौखलाहट उसकी पहचान है।' एक अन्य यूजर ने कमेंट में किया, 'आपके पोस्ट समझ नहीं आते हैं और किसी को बच्चन साहब।'

एक्टर को लेकर उड़ी थी अफवाह

अभिनेता अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर मंगलवार को एक बड़ी खबर सामने आई थी। कहा जा रहा थी कि वह दो दिन से बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। यह खबर सामने आते ही उनके फैंस परेशान हो गए थे। मगर दो दिन के अंतराल के बाद एक्टर ने खुद ट्वीट और ब्लॉग पोस्ट कर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। बाद में कहा गया कि वो सिर्फ रुटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com